● वर्ष-3
● अंक-129
रायपुर, रविवार
07 जनवरी 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› आलिया की जगह वरुण की...

भारत की बड़ी कामयाबी

सूरज के एल1 प्वाइंट पर पहुंचा आदित्य यान

हरिकोटा। देश की पहली सौर वेधशाला 'आदित्य-एल1' अपने गंतव्य तक पहुंच गई है। 110 दिनों की यात्रा, 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने और बाद में एक सटीक कक्षा में प्रवेश के बाद, आदित्य-एल1 मिशन को अंतरिक्ष की विशालता में एक इष्टतम स्थान पर सफलतापूर्वक पार्क किया गया है, जहां से उसे सूर्य का अबाधित दृश्य दिखाई देगा। प्रभामंडल कक्षा, एल 1 , एल 2 या एल 3 'लैग्रेंज प्वाइंट' में से एक के पास एक आवधिक, त्रि-आयामी कक्षा है। इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी-सी57) ने दो सितंबर को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी) के दूसरे प्रक्षेपण केंद्र से आदित्य-एल1 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। पीएसएलवी ने 63 मिनट और 20 सेकंड की उड़ान के बाद उसने पृथ्वी की आसपास की अंडाकार कक्षा में आदित्य-एल1 को स्थापित किया था। 'आदित्य एल1' को सूर्य परिमंडल के दूरस्थ अवलोकन और पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर 'एल1' (सूर्य-पृथ्वी लैग्रेंजियन बिंदु) पर सौर वायु का वास्तविक अवलोकन करने के लिए डिजाइन किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इस मिशन का मुख्य उद्देश्य सौर वातावरण में गतिशीलता, सूर्य के परिमंडल की गर्मी, सूर्य की सतह पर सौर भूकंप या 'कोरोनल मास इजेक्शन' (सीएमई), सूर्य के धधकने संबंधी गतिविधियों और उनकी विशेषताओं तथा पृथ्वी के करीब अंतरिक्ष में मौसम संबंधी समस्याओं को समझना है।

वैज्ञानिकों के अथक समर्पण को प्रणाम: मोदी- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने खबर साझा की और कहा कि भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की है। भारत की पहली सौर वेधशाला, आदित्य-एल1 अपने गंतव्य तक पहुंच गई है। इसको लेकर उन्होंने एक एक्स पोस्ट लिखा। अपने पोस्ट में लिखा कि भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की। भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य-एल1 अपने गंतव्य तक पहुंची। यह सबसे जटिल और पेचीदा अंतरिक्ष अभियानों को साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है।

इसरो को बधाई: मुर्मू- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को भारत के पहले सूर्य मिशन 'आदित्य-एल1' को उसकी गंतव्य कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिएभारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को बधाई दी और कहा कि इस अभियान से पूरी मानवता को लाभ होगा।

भारत की यात्रा एक और मील का पत्थर: शाह - गृह मंत्री अमित शाह ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''अंतरिक्ष के माध्यम से भारत की यात्रा में एक और मील का पत्थर!! हमारा पहला सौर अनुसंधान उपग्रह आदित्य-एल1 अंतरिक्ष में अपने गंतव्य तक पहुंच गया है। यह इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है जो हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता के माध्यम से मानव कल्याण प्राप्त करने के हमारे सभ्यतागत लक्ष्य के करीब ले जाती है। उन्होंने कहा, ''हमारे प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों और हमारे देश के लोगों को मेरी हार्दिक बधाई।

सफलता से गदगद इसरो चीफ ने बताया आगे का प्लान, बोले- अगले कुछ घंटों तक रखेंगे नजर

इसरो के सौर मिशन, आदित्य-एल1 पर हालिया अपडेट में, इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने अंतरिक्ष यान के सटीक हेलो कक्षा में सफल प्रवेश के बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने उल्लेख किया कि यद्यपि उच्च कक्षा की ओर बढ़ने के दौरान कुछ सुधारों की आवश्यकता थी, वर्तमान गणना से पता चलता है कि आदित्य-एल1 सही स्थिति में है। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि आज का कार्यक्रम केवल आदित्य-एल1 को सटीक हेलो कक्षा में स्थापित करना था। तो यह एक उच्च कक्षा की ओर बढ़ रहा था, लेकिन हमें थोड़ा सुधार करना पड़ा... इसलिए अभी, हमारी गणना में, यह सही जगह पर है। लेकिन हम अगले कुछ घंटों तक इस पर नजर रखेंगे कि यह सही जगह पर है या नहीं। फिर अगर इसमें थोड़ा सा भी बदलाव हुआ तो हमें थोड़ा सुधार करना पड़ सकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इसरो अपने स्थान की बारीकी से निगरानी कर रहा है और यदि कोई मामूली गड़बड़ी होती है, तो वे आवश्यक सुधार करने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष ने साझा किया कि मिशन की छवियां पहले ही वेबसाइट पर जारी की जा चुकी हैं, जिसमें सूर्य से आने वाले कण माप के डेटा को प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने एक्स-रे माप के महत्व पर प्रकाश डाला, जो निम्न और उच्च ऊर्जा श्रेणियों दोनों को कवर करता है.

चीन का अब तक का सबसे बड़ा अतिक्रमण

भूटान के शाही परिवार के पैतृक क्षेत्रों पर किया कब्जा

नई दिल्ली। दुनिया के कई देश चीन के विस्तारवादी नीतियों से परेशान हैं. चीन की गलत नीतियों का ताजा शिकार भूटान होता दिख रहा है. कुछ नए सैटेलाइट इमेज में सामने आए हैं जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह चीन भूटान के बेयुल खेनपाजोंग में एक नदी घाटी के किनारे टाउनशिप का निर्माण कर रहा है. चीन निर्माण के माध्यम से पूर्वोत्तर भूटान में अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास कर रहा है. चीन की तरफ से इस तरह का निर्माण ऐसे समय में किया जा रहा है जबकि दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर वार्ता जारी है. जकारलुंग क्षेत्र में निर्माण से चीन ने साफ संकेत दे दिया है कि वो इस क्षेत्र पर अपने दावों को किसी भी हालत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है.

इस मामले पर लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज (एसओएएस) में तिब्बती इतिहास के विशेषज्ञ, प्रोफेसर रॉबर्ट बार्नेट ने कहा है कि यह चीन की तरफ से एक कमजोर पड़ोसी देश के सांस्कृतिक महत्व वाले क्षेत्र पर अवैध कब्जा की तरह है.

बेयुल खेनपाजोंग में चीन की निर्माण गतिविधि पर सवालों के जवाब में, भारत में भूटान के राजदूत मेजर जनरल वेत्सोप नामग्याल (सेवानिवृत्त) ने कहा कि हालांकि यह हमारी नीति है कि हम चल रही किसी भी सीमा वार्ता को लेकर मीडिया में कोई बयान नहीं देते हैं. लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि हम सीमा वार्ता के दौरान हमेशा भूटान के क्षेत्रीय हितों को बनाए रखा जाएगा और उसकी रक्षा की जाएगी. सैटेलाइट इमेजरी विशेषज्ञों ने एनडीटीवी से बात करते हुए बताया कि इन तस्वीरों से साफ हो रहा है कि चीन ने जिस स्तर का निर्माण कार्य किया है उसमें सैंकड़ों लोगों को बसाया जा सकता है. हालांकि यह माना जा रहा है कि कि अंतिम संख्या इससे अधिक हो सकती है. यहां दिखाई देने वाले तीन एन्क्लेव का निर्माण अभी भी पूरा नहीं हुआ है.

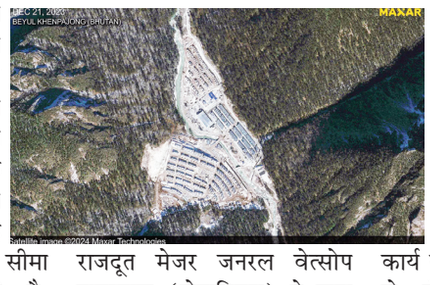

रेफरेंस के लिए हम आपको नवंबर 2020 की पुरानी तस्वीरों को भी नई तस्वीर के साथ दिखा रहे हैं. जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उस दौरान उस क्षेत्र में निर्माण कार्य नहीं हुए थे. नवंबर 2020 से लेकर अब तक बेयुल खेनपाजोंग को पूरी तरह से बदल दिया गया है. सड़क का एक जाल बिछा दिया गया है. चैथम हाउस द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक लेख में, जॉन पोलक और एक प्रमुख भू-खुफिया शोधकर्ता डेमियन साइमन ने बेयुल, और अन्य घाटियों के महत्व को समझाया है.

जो महिलाएं हिजाब नहीं पहनतीं चरित्रहीन हैं.., मौलवी पर मामला दर्ज

केरल में एक मुस्लिम धर्मगुरु उमर फैजी मुक्कम के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं पर उनकी कथित टिप्पणी के लिए मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा था कि जो महिलाएं हिजाब नहीं पहनती हैं, उनकी नैतिक नैतिकता होती है। उन्होंने यह कथित टिप्पणी 7 अक्टूबर, 2023 को प्रसारित एक टेलीविजन बहस के दौरान की थी। केरल पुलिस ने शुक्रवार को एक महिला अधिकार कार्यकर्ता की शिकायत के बाद समस्त केरल जमियथुल उलमा नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया। उमर फैजी पर आईपीसी की धारा 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) और धारा 298 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। महिला अधिकार कार्यकर्ता वीपी जुहारा ने तीन महीने पहले शिकायत दर्ज की थी। हालाँकि, मामला शुक्रवार को ही दर्ज किया गया था।

प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रथम बस्तर आगमन पर बस्तरवासियों ने जगदलपुर शहर के विभिन्न चौक-चौराहों में पारम्परिक लोक नृत्यों और पुष्प वर्षा सहित शंखनाद से जोशीला स्वागत किया।

एकनाथ ने राम मंदिर को दान में दिए 11 करोड़

मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने शनिवार को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए 11 करोड़ रुपये का दान दिया। पार्टी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें पार्टी सांसद श्रीकांत शिंदे, महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत, पार्टी प्रवक्ता नरेश म्हस्के, आशीष कुलकर्णी और पार्टी सचिव भाऊ चौधरी शामिल थे, ने श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय से मुलाकात की और 11 करोड़ रुपये का चेक सौंपा। उदय सामंत ने कहा कि महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र की जनता और शिवसेना की ओर से राम मंदिर के लिए 11 करोड़ रुपये दिए हैं। आज हम यहां चेक सौंपने आये हैं। वहीं, चंपत राय ने कहा कि यह खुशी की बात है कि महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत और शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के सांसद श्रीकांत शिंदे महाराष्ट्र के लोगों की ओर से 11 करोड़ रुपये का चेक सौंपने यहां आए। राशि बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई है। राम मंदिर का अभिषेक 22 जनवरी को होगा। इससे पहले मुंबई में एक स्वच्छता अभियान को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा, ''राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को किया जाएगा।

प्रमुख समाचार

अजय माकन, जयराम रमेश बने प्रचार समिति के सदस्य

नई दिल्ली। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी तेज करते हुए शनिवार (6 जनवरी) को एक प्रचार समिति का गठन किया. पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन इस समिति के संयोजक होंगे. पार्टी के महासचिव जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल इसके सदस्य बनाए गए हैं. पार्टी की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि आम चुनावों के लिए एक सेंट्रल वार रूम भी बनाया है, जिसके संचार वार रूम का नेतृत्व वैभव वालिया करेंगे, जबकि संगठनात्मक वार रूम की अध्यक्षता शशिकांत सेंथिल एस करेंगे. कांग्रेस के बयान के मुताबिक वरुण संतोष, गोकुल बुटेल, नवीन शर्मा और कैप्टन अरविंद कुमार संगठनात्मक वार रूम में उपाध्यक्ष होंगे. बयान के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आगामी लोकसभा आम चुनाव के लिए प्रचार समिति का गठन किया है, जिसके संयोजक पार्टी कोषाध्यक्ष होंगे. इसके अनुसार, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महासचिव, पार्टी महासचिव, प्रशासनिक विभाग के प्रभारी, मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख और सोशल मीडिया विभाग के प्रमुख इसके सदस्य होंगे. बयान के अनुसार, एआईसीसी महासचिव वेणुगोपाल, संचार विभाग के प्रभारी पार्टी महासचिव रमेश, प्रशासनिक विभाग के प्रभारी गुरदीप सिंह सप्पल , मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा और सोशल मीडिया विभाग की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत हैं.

भोपाल के अवैध हॉस्टल से 26 लड़कियां लापता

भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक एनजीओ के अवैध हॉस्टल से एक बच्चे और 26 बच्चियों के गायब होने का आरोप है. हॉस्टल में बच्चियों से ईसाई धर्म की प्रैक्टिस करवाई जाती थी. एक बच्ची से भगवान की मूर्ति विसर्जित करवाने की बात भी सामने आई है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने जब इस छात्रावास का निरीक्षण किया तो कई चौंकाने वाली बातों का पता चला है. छात्रावास में ईसाई धर्म की प्रैक्टिस का भी आरोप है, दस्तावेज़ों में 68 बच्चों के रहने की एंट्री है. यहां सिर्फ़ 41 बच्चियां मिली है ,ये बच्चियां एमपी ,गुजरात झारखंड से हैं. राष्ट्रीय बाल आयोग ने संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव वीरा राणा से सात दिन में जांच रिपोर्ट मांगी है, परवलिया पुलिस ने हॉस्टल संचालक और पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. पूरे मामले पर एसडीओपी मंजू तिवारी ने कहा कि जो अपराध पंजीबद्ध हुआ है उसकी हम इन्वेस्टीगेशन कर रहे हैं. जानकारी जुटायी जा रही है उस हिसाब से कार्रवाई होगी. परवलिया थाना क्षेत्र में अपराध पंजीबद्ध हुआ है छुछु एक्ट के तहत केस दर्ज किए गए हैं.कार्रवाई नॉर्म्स के हिसाब से की जाएगी.

20 से 26 जनवरी तक घरों में रहें मुसलमान: गिरिराज

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शनिवार को ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल की उस टिप्पणी पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर मुसलमानों से 20 से 26 जनवरी के बीच घर पर रहने को कहा था। गिरिराज सिंह ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों से नफरत नहीं करती। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ काम करते हैं। अयोध्या भूमि विवाद मामले के पूर्व वादी इकबाल अंसारी को राम मंदिर के अभिषेक समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है और वह प्रार्थना में भी भाग लेंगे। भाजपा नेता ने साफ तौर पर कहा कि बदरुद्दीन अजमल, औवेसी जैसे लोग समाज में नफरत फैलाते हैं। बीजेपी सभी धर्मों का सम्मान करती है। एक रिपोर्ट के अनुसार, कहा जाता है कि अजमल ने मुसलमानों से 20 से 26 जनवरी के बीच घर पर रहने और उस अवधि में अयोध्या में होने वाले राम मंदिर अभिषेक समारोह के दौरान ट्रेनों में यात्रा करने से बचने के लिए कहा है। अयोध्या में राम मंदिर का अभिषेक समारोह 22 जनवरी को होगा।

उद्धव को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का नहीं मिला निमंत्रण

मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण नहीं मिला है। शिवसेना (यूबीटी) गुट प्रमुख ने शनिवार को कहा कि वह और उनकी पार्टी के नेता उस दिन नासिक में कालाराम मंदिर जाएंगे और गोदावरी नदी के तट पर महा आरती करेंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का अभिषेक समारोह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत देश-विदेश से कई वीवीआईपी मेहमान प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। शिवसेना (यूबीटी) नेता ने कहा कि अयोध्या राम मंदिर का अभिषेक गौरव और स्वाभिमान का विषय है। उस दिन (22 जनवरी) शाम 6.30 बजे हम कालाराम मंदिर जाएंगे। जहां डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर और (समाज सुधारक) साने गुरुजी को विरोध प्रदर्शन करना था।

सांस्कृतिक विकास पर काम कर रही सरकार -राजनाथ सिंह

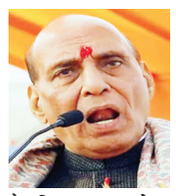

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि लॉर्ड मैकाले को देश की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को खत्म करने और लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए भारत भेजा गया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार सांस्कृतिक विकास पर काम कर रही है ताकि आने वाली पीढ़ियां इस पर गर्व कर सकें। शनिवार को पतंजलि गुरुकुलम एवं आचार्यकुलम के शिलान्यास समारोह में बतौर मुख्य अतिथि रक्षामंत्री पहुंचे हरिद्वार पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत में हर शास्त्र व हर पंथ गुरु के महत्व को स्वीकार करता है। गुरु के महत्व को सब ने माना है। गुरु-शिष्य की बड़ी विशिष्ट परंपरा रही है हमारे देश में। यह वह देश है, जहाँ गुरुवाणी और गुरुग्रंथ को ईश्वर का दर्जा दे दिया जाता है, तो शिष्य के नाम पर पूरा पंथ प्रारंभ हो जाता है। राजनाथ ने कहा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय से लेकर विक्रमशिला विश्वविद्यालय होते हुए नालंदा विश्वविद्यालय तक इस देश में अनेक ऐसे संस्थान थे, जिन्होंने शिक्षा की ऐसी अलख जगाई थी, जिससे समूचा विश्व दीप्तिमान होता था। जहां दर्शन, गणित, विज्ञान, चिकित्सा व कला आदि विद्याओं का ज्ञान दिया जाता था।

ईडी के समन की अवहेलना कर कानून को मुंह चिढ़ा रहे हैं दो मुख्यमंत्री

डॉ. आशीष वशिष्ठ

इन दिनों देश में दो मुख्यमंत्री कानून और जांच एजेंसियों को मुंह चिढ़ा रहे हैं। इनमें पहले मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और दूसरे झारखंड के हेमन्त सोरेन हैं। दोनों मुख्यमंत्रियों को भ्रष्टाचार से जुड़े अलग-अलग मामलों में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी कई दफा नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुला चुकी है। लेकिन दोनों ईडी के सामने पेश न होने के बहाने बना रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत को ईडी सात बार और केजरीवाल को तीन बार समन भेजी चुकी है। लेकिन दोनों पूरी ढिठाई और बेशर्मी से इस मामले में पॉलिटिकल विक्टिम कार्ड का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हैं। और केंद्र की मोदी सरकार पर अपने विरोधियों को दबाने के लिए जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं। असल में राजनीतिक आरोपों के आड़ में ये दोनों खुले तौर पर कानून और जांच एजेंसियों का मजाक उड़ा रहे हैं। बीती 3 जनवरी को अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाला केस में ईडी ने तीसरा नोटिस देकर बुलाया था। लेकिन केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से इंकार कर दिया। उन्होंने ईडी को जवाब भेजकर समन को अवैध करार दिया। जिस शराब घोटाले में केजरीवाल से पूछताछ होनी है, उस मामले में उनके दो बड़े नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह महीनों से तिहाड़ में बंद हैं। मामला गंभीर है। जांच में केजरीवाल का नाम सामने आने के बाद से यह साफ है कि एजेंसी के पास उनके खिलाफ ठोस सुबूत होंगे। इस मामले में सीबीआई उनसे पूछताछ कर चुकी है। केजरीवाल अक्सर मीडिया और सार्वजनिक मंचों से छाती ठोककर खुद अपने को ईमानदारी का प्रमाण पत्र देते हैं। दस साल पुरानी आम आदमी पार्टी के दिल्ली और पंजाब के लगभग 20 नेता विभिन्न मामलों में जेल की सैर कर चुके हैं। इन दोनों राज्यों में आप की सरकार है।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी को जमीन घोटाले और अवैध खनन मामले में पूछताछ करनी है। ईडी उन्हें सात समन भेज चुकी है। लेकिन हेमंत लगातार पूछताछ से भाग रहे हैं। ईडी ने अपने सातवें समन में मुख्यमंत्री से यह पूछा था कि वो स्वयं पूछताछ के लिए जगह तिथि व समय बता दें, ताकि पूछताछ की जा सके। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो जवाब भेजा है उसमें जगह तिथि व समय का जिक्र नहीं है।

केजरीवाल और सोरेन ही नहीं विपक्ष के जिस नेता के यहां जांच एजेंसियां पहुंचती हैं, वो इसे राजनीति से प्रेरित बताकर राजनीतिक ड्रामा करने लगता है। बीते दिनों झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से इनकम टैक्स की छापेमारी के दौरान 353 करोड़ से ज्यादा की नगदी बारामदगी हुई है। इस मामले पर भी जमकर राजनीति हुई। पश्चिम बंगाल में बीती जुलाई में, टीएमसी नेता एवं राज्य के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को स्कूल नौकरी घोटाले से जुड़े एक मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इस साल की शुरुआत में, टीएमसी सांसद और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग भर्ती और कोयला तस्करी मामलों के संबंध में पूछताछ की गई थी। राशन वितरण घोटाले में ममता सरकार के राज्य मंत्री मलिक को ईडी ने गिरफ्तार किया था।

फरवरी 2019 में सीबीआई की एक टीम कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से शारदा चिट फंड घोटाले में पूछताछ करने आई तो सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और धरने पर बैठ गई थी। शारदा समूह ने पश्चिम बंगाल में कई पोंजी योजनाओं के जरिये कथित तौर पर लाखों लोगों को ठगा। इसमें तृणमूल कांग्रेस नेताओं के नाम सामने आए थे। सीबीआई उसकी जांच कर रही है तो राज्य सरकार ने राजनीतिक कारणों से उसे रोकने का काम किया। बिहार में लालू यादव और उनके परिवार के सदस्य भ्रष्टाचार के मामले में जांच का सामना कर रहा है। भ्रष्टाचार और अपराध में लिप्त पक्ष और विपक्ष के तमाम नेता जांच एजेंसियों के राडार पर हैं। कई नेता जेल की सजा भी काट रहे हैं। सीधी-सी बात है अगर किसी का दामन पाक साफ है तो उसे जांच एजेंसी पूछताछ के लिए क्यों बुलाएगी? अगर कोई बेगुनाह है तो उसे अदालत सजा क्यों देगी? अदालत या जज किसी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता नहीं हैं। दिल्ली शराब घोटाले में सिसोदिया और संजय सिंह को कोर्ट जमानत नहीं दे रहा। मतलब अदालत यह समझती है कि इन दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, अगर इनको जमानत दी गई तो ये लोग जांच को प्रभावित कर सकते हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री आजम खां, उनकी पत्नी और बेटा जेल में बंद हैं। लालू प्रसाद यादव चारे घोटाले में सजायाफ्ता हैं। क्या बिना किसी कसूर के अदालत ने उन्हें सजा सुनाई है। भ्रष्टाचार के एक मामले में बीती 22 दिसंबर को यूपी में बसपा सरकार में शिक्षा मंत्री रहे राकेश धर त्रिपाठी को 3 साल कैद की सजा हुई है। बीती 21 दिसंबर को मद्रास हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में डीएमके नेता और तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी को दोषी ठहराते हुए तीन साल की कैद और 50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पोनमुडी की पत्नी विशालाक्षी को भी दोषी ठहराया गया है। सवाल यह है कि, क्या इन नेताओं को अदालत से मिली सजा राजनीति से प्रेरित है? वास्तव में, राजनीतिक भ्रष्टाचार पर राजनीतिक दलों के बीच गजब का आपसी तालमेल और सहमति का इतिहास रहा है। सार्वजनिक मंचों से एक दूसरे के खिलाफ चाहे कितना भी कीचड़ उछाला जाए, लेकिन चुनाव बाद भ्रष्टाचार की बात नहीं होती थी। लेकिन 2014 में केंद्र की मोदी सरकार आने के बाद से भ्रष्टाचार खासकर राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ चली आ रही सहमति और तालमेल पर जोरदार प्रहार किया गया।

विकसित भारत संकल्प यात्रा में पटवारी पर लगा रिश्वत लेने का आरोप

विधायक ने जताई नाराजगी, सस्पेंड करने के दिए निर्देश

राजिम। ग्राम पंचायत तरीघाट में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचे मुख्य अतिथि विधायक रोहित साहू का ग्रामवासियों ने बाजे-गाजे और जमकर आतिशबाजी के साथ भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाया था, जहां ग्रामीण अपनी मुलभूत सुविधाओं सहित रोजगार मूलक मांगों को लेकर आवेदन किया। कार्यक्रम में एक किसान ने विधायक के सामने पटवारी पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। इस पर विधायक ने नाराजगी जताते हुए नायब तहसीलदार शशि नर्मदा को जांच कर तुरंत सस्पेंड करने की बात कही।

जनशैलाब को संबोधित करते हुए नवनिर्वाचित विधायक रोहित साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राजिम में कमल फूल खिलाने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। विधायक साहू ने कहा, गांव-गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाकर आप लोगों की समस्या का निराकरण करने के लिए चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान तरीघाट निवासी किसान श्याम लाल साहू ने पटवारी कोमल लाल वर्मा पर 1600 रुपए की रिश्वत लेने की बात खुली मंच पर रखी। किसान ने पैसे की बात तो कह दी मगर कितने रुपए लिए उसे बोल नहीं पा रहे थे, जिस पर विधायक ने बिना डर भय बोलने को कहा। फिर किसान ने बताया कि मेरे नाम पर 5 काठा का खेत होने की जानकारी पटवारी द्वारा दिए जाने पर उन्होंने कहां था रिकार्ड दुरुस्त कर आपको जमीन मिल जाएगी। इसके चलते उनके द्वारा पैसे की मांग करने पर मेरे द्वारा ग़रीबी व तंग हाल जिंदगी जीने के चलते 1600 रुपए दिया गया था।

किसान ने बताया कि तकरीबन साल गुजर जाने के बाद भी पटवारी ने मुझे जमीन नहीं दिया। इस संबंध में पूछने पर कुछ बताया नहीं जा रहा। इसके चलते मुझे किसान समान निधि का पैसा नहीं मिल पा रहा है। मौके पर किसान द्वारा आपबीती बताए जाने पर विधायक ने नाराजगी जताते हुए नायब तहसीलदार शशि नर्मदा को जांच कर तुरंत सस्पेंड करने की बात कही। विधायक ने सर्व समाज के लिए टीनासेट बर्तन जैसे सर्वजनिक कार्य के लिए घोषणा की। आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 3 पहुंचकर विधायक ने पूजा-अर्चना कर फीटा काट कर लोकार्पण भी किया।

इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व सरपंच व वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी विजय कंडरा जिला उपाध्यक्ष भाजपा राजू साहू, बोधन साहू, सरपंच जया साहू, पंच कोमल साहू, चिमन वर्मा, युगल साहू सहित पार्टी के कार्यकर्ता व ग्रामवासी एवं पंच उपस्थित थे। विधायक रोहित साहू आज विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर तरीघाट पहुंचे, जहां सरकार की योजनाओं से लाभान्वित व सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया।

रेल अंडरब्रिज की मांग, रेलवे का इनकार धनगवां के ग्रामीणों ने खोला मोर्चा

गौरेला पेंड्रा मरवाही। पेंड्रारोड से लेकर गेवरारोड तक नई रेल लाइन बिछाने का काम चल रहा है।जिले लेकर अब धनगवा गांव के लोगों ने मोर्चा खोला है। ग्रामीण गांव और रेल लाइन के बीच अंडर ब्रिज नहीं बनाने को लेकर नाराज हैं।ग्रामीणों के मुताबिक यदि रेल अंडरब्रिज नहीं बना तो गांव नजदीकी सड़क से कट जाएगा।ऐसे में उन्हें ज्यादा दूरी तय करके मुख्य मार्ग तक पहुंचना होगा।इसके लिए ग्रामीणों ने कलेक्टर से गुहार लगाई थी।लेकिन एक घंटे तक हुई बातचीत का कोई भी हल नहीं निकला।

दो दिन पहले ग्रामीणों ने करवाया था काम बंद

दो दिन पहले गौरेला ब्लॉक के धनगवा गांव के ग्रामीणों ने छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेल कॉरिडोर का काम बंद करवा दिया था। रेल लाइन पेंड्रारोड से गेवरारोड तक बनाई जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि रेलवे जमीन की सतह के लगभग 50 फीट ऊपर पर रेलवे ट्रैक बना रही है। जिसमें धनगवा गांव के पास एक बड़ी आबादी का हिस्सा रेलवे ट्रैक के 2 किलोमीटर के दायरे में हैं। जिसमें मात्र दो अंडर ब्रिज का ही निर्माण किया है जिसमें एक अंडर ब्रिज तो नाले का पानी निकासी के लिए है।रेलवे ब्रिज ना होने से पुरानी सड़क दो हिस्सों में बंट जाएगी और गांव भी दो भागों में हो जाएगा।

नया अंडरब्रिज बनाने से इनकार

ग्रामीणों के मुताबिक निस्तार के साथ-साथ गांव से लगे दूसरे दर्जन भर गांव रेल अंडरब्रिज नहीं बनने के कारण एक दूसरे से कट जाएंगे। जिससे लोगों को काफी परेशानी होगी। अपनी तकलीफ को लेकर ग्रामीण काम रूकवाने के बाद कलेक्टर के पास पहुंचे थे।जिसमें गांवों के सरपंचों ने कलेक्टर से अंडर ब्रिज की गुहार लगाई थी।जिस पर ग्रामीणों को बताया गया कि जिस जगह पर अंडरब्रिज की मांग हो रही है। वहां एक छोटा और एक बड़ा अंडरब्रिज पहले से बना है। अब नया अंडरब्रिज बनाना संभव नहीं है।

कलेक्टर प्रियंका ऋषि महोबिया ने कहा रेलवे के अधिकारियों के साथ मीटिंग की है।जिसमें उन्होंने बताया कि दो जगहों पर रेल अंडरब्रिज बनाया गया है।साथ ही रेलवे ठेकेदार को ट्रैक के दोनों ओर पक्की निस्तारी सड़क बनाने को कहा गया है।

क्या है ग्रामीणों का आरोप

वही ग्रामीणों के मुताबिक अधिकारियों ने सुविधा देने की बात तो कही है। लेकिन रेल अंडरब्रिज बनाने की मांग को खारिज कर दिया है।कोई भी अधिकारी मामले में खुलकर जवाब देने की स्थिति में नही है।

अब ग्रामीण भी रेल लाइन में अंडर ब्रिज की मांग को लेकर आरपार की लड़ाई के मूड पर है और आगे तक जाने की बात कह रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन का दावा है कि रेलवे ट्रैक में अंडर ब्रिज नहीं बनने से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी।

रेलवे स्टेशन में पार्किंग ठेकेदार की मनमानी पर भड़के हाईकोर्ट चीफ जस्टिस

कहा - कहां है डीआरएम, जाकर देखें स्टेशन की हालात

बिलासपुर। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप एंड गो में बैरियर लगाकर ठेकेदार की अवैध वसूली को लेकर जमकर नाराजगी जताई। मामले की सुनवाई के दौरान डीआरएम का जवाब पढ़कर चीफ जस्टिस नाराज हुए। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा रेलवे स्टेशन चला रहे हो, हजारों यात्रियों का आना-जाना है, उनसे कोई मतलब है या नहीं। रेलवे स्टेशन पर मनमानी चल रही है, कहां है डीआरएम, ऑफिस से निकलकर रेलवे स्टेशन जाकर देखें कि क्या हालात है, यहां कोई सिस्टम है या नहीं।

बता दें कि रेलवे की अव्यवस्था को लेकर मीडिया की खबर को हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है और मामले की जनहित याचिका मानकर केस की सुनवाई चल रही है। मामले की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रेलवे डीआरएम को शपथपत्र के साथ जवाब प्रस्तुत करने कहा था। इसके बाद आनन-फानन में रेलवे के अफसरों ने दिखावे के लिए वाणिज्य निरीक्षक को सस्पेंड कर दिया। साथ ही ठेकेदार पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया। डीआरएम के जवाब में इसका भी जिक्र किया गया था।

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के बिलासपुर डीआरएम की तरफ से शपथ पत्र के साथ जवाब प्रस्तुत किया गया। सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा कि रेलवे है, अस्पताल है, यहां लोग किस तरह की अव्यवस्था से गुजर रहे हैं, कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस बात की चिंता आप लोगों को है भी या नहीं। न तो रेलवे की व्यवस्था सुधर रही है और न ही अस्पताल की। यहां सिस्टम नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। लोगों को सुविधा मुहैया कराने के बजाय परेशानी ही खड़ी करते रहेंगे क्या? ऐसा काम क्यों करते हैं, जिससे लोगों की परेशानी हो।

विस्फोटक के साथ एक नक्सली गिरफ्तार आयतु को न्यायालय में किया गया पेश

बीजापुर। बीजापुर जिले में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत बीते दिनों पुलिस को देखकर भाग रहे एक नक्सली को विस्फोटक के साथ सुरक्षाबल के जवानों ने गिरफ्तार किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बीते दिनों डीआरजी, बस्तर फाइटर और सीआरपीएफ की संयुक्त पार्टी नक्सल विरोधी अभियान पर गंगालूर थाना क्षेत्र के कुरुष व पुसनार की तरफ निकली हुई थी। इस दौरान कुरुष के जंगल में पुलिस पार्टी को देख भाग रहे एक संदिग्ध को जवानों द्वारा पकड़ा गया।

पकड़े गये नक्सली के पास से एक थैले में इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, कॉर्डेक्स वायर, जिलेटिन स्टीक, स्वीच प्रतिबंधित माओवादी संगठन के प्रचार प्रसार की सामाग्री पाम्पलेट व अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई हैं। पूछताछ पर उसने अपना नाम जनमिलिशिया सदस्य आयतु परसीक पिता सन्नू परसीक उम्र 23 निवासी कुरुष का होना बताया। पकड़े गए संदिग्ध के खिलाफ गंगालूर थाना में वैधानिक कार्रवाई के बाद न्यायिक रिमांड पर न्यायालय बीजापुर में पेश किया गया है।

नक्सलियों के पीएलजीए बटालियन नंबर-1 के गढ़ मुखराजकोंडा में खुला कैंप

सुकमा। जिले के घुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के थाना चिंतागुफा अंतर्गत ग्राम दुलेर के पास मुखराजकोंडा में नक्सलियों के पीएलजीए बटालियन नंबर-01 के गढ़ कहे जाने वाले क्षेत्र में नवीन कैंप स्थापित किया गया। डीआरजी,बस्तर फाइटर,कोबरा 206 वाहिनी, 02 वाहिनी सीआरपीएफ एवं जिला बल के विशेष सहयोग से नवीन कैंप स्थापित किया गया। नवीन कैंप स्थापित होने से नक्सलियों के पीएलजीए बटालियन के खिलाफ अभियान में तेजी आएगी। नवीन कैंप स्थापना होने से नक्सलियों के गढ़ कहे जाने इलाके में ग्रामीणों के मन से नक्सली दहशत समाप्त होगा, इसके साथ ही स्थानीय ग्रामीण मुख्यधारा से जुड़ेंगें और लोगों को शासन-प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे विकासात्मक कार्यों जैसे सड़क, पुल-पुलिया, भवन बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं, मोबाईल कनेक्टिविटी एवं जन कल्याणकारी योजनाओं लाभ मिलेगा।

शक्कर कारखाना के संविदा कर्मचारी 9 से करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल

कबीरधाम। कबीरधाम जिले के पंडरिया स्तिथ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना के संविदा कर्मचारी हड़ताल की राह पर हैं। इसे लेकर यहां के कर्मचारियों ने जिला प्रशासन व कारखाना प्रबंधन को ज्ञापन भी दिया गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि सभी संविदा कर्मचारियों द्वारा ग्रेड वेतन विसंगति सुधार कर वेतनमान संशोधन करने की मांग को लेकर बीते साल 22 सितंबर 2023 को अनिश्चिकालीन हड़ताल की गई थी।

इसके बाद कारखाना प्रबंधन द्वारा लिखित में उक्त मांग को पूरा कर माह सितम्बर-अक्तूबर 2023 से बढ़ा हुआ वेतन दिए जाने का आश्वासन दिया गया था, जिस पर संविदा कर्मचारी समझौता की शर्त पर हड़ताल समाप्त कर वापस काम पर लौट आए थे। लेकिन, अब तक कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं हुई। ऐसे में अब फिर से मांगों को लेकर 9 जनवरी को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं।इनके हड़ताल में चले जाने से पेराई सत्र 2023-24 संचालन प्रभावित होगी। वर्तमान में इस कारखाना में पेराई जारी है। इन कर्मचारियों की प्रमुख मांग स्टापिंग पैटर्न के ग्रेड विसंगति एवं वेतनमान सुधारकर वेतन वृद्धि करने व वेतन वृद्धि कर सितम्बर 2023 से नवम्बर 2023 का एरियस दिए जाने की है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

22 को शा. अवकाश घोषित करने सीएम को सौंपा ज्ञापन

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रथम नगर आगमन पर सर्व हिन्दू समाज बस्तर के द्वारा अनुपमा चौक में स्वागत किया गया। इस दौरान श्रीराम जन्मभूमि आयोध्या धाम में जन-जन के आराध्य प्रभु श्रीराम जी के बालरूप की प्राण-प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर 22 जनवरी सोमवार को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश में शासकीय अवकाश घोषित करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। सर्व हिन्दू समाज बस्तर के सचिव एल. ईश्वर राव ने बताया कि आगामी पौष शुक्ल द्वादशी, विक्रम सम्वत 2080, सोमवार, दिनांक 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्रीराम के बाल रूप की नूतन विग्रह को श्रीराम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर के भूतल गर्भगृह में प्राण-प्रतिष्ठा किया जाना है। जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रत्येक ग्राम नगर के मंदिरों में भी पूजन, उत्सव महोत्सव मनाया जाएगा। चूंकि यह कार्यक्रम सोमवार शासकीय कार्यदिवस होने के कारण शासकीय कर्मचारी एवं स्कूल, कॉलेज के बच्चे वंचित होंगे। सर्व हिन्दू समाज ने मुख्यमंत्री से ज्ञापन सौंपा कर प्रदेश में 22 जनवरी को शासकीय अवकाश घोषित किये जाने अनुरोध किया है।

बारिश ने बढ़ाई ठंड, कोहरे ने वाहनों पर लगाए ब्रेक

गौरेला पेंड्रा मरवाही। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में देररात से मौसम ने करवट ली है। रुक-रुककर हो रही बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। कई इलाकों में कोहरा छाया रहा। ठंड ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है, कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार कम हो गई हैं। दरअसल, कल देररात से जिले में मौसम ने करवट ली है। आसमानों में बादलो का डेरा रहा तो नार्थ छत्तीसगढ़ में इसका असर दिखाई दे रहा है और आज सुबह से रुक रुककर बारिश के चलते तापमान में गिरावट भी देखने को मिली है। इलाके में घना कोहरा छा गया जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। जिसके चलते सड़को में वाहनों की रफ्तार में भी कोहरे के असर दिखाई दिया। बारिश के बाद ठंड बढ़ने से तो कोहरे का असर ट्रेन की रफ्तार पर भी पड़ा है ट्रेन अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही है। तो ग्रामीण इलाकों और अमरकंटक की तराई में स्थित छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाको में रहने वाले ग्रामीणों की समस्या भी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में ठंड अपने पूरे चरम पर रहने के आसार हैं।

कोंडागांव में संदिग्ध स्थिति में सीआईएसएफ जवान की मौत

कोंडागांव। सिटी कोतवाली कोंडागांव अंतर्गत बनियागांव में एक सीआईएसएफ के जवान की संदिग्ध हालत से मौत हो गई। जवान अच्छा खासा था। हर रोज की तरह घर में अपना काम कर रहा था लेकिन इसी दौरान अचानक बेहोश हुआ और तुरंत उसकी मौत हो गई। जवान दिल्ली मेट्रों में सीआईएसएफ जवान के पद पर पदस्थ था और छुट्टियों में घर आया था। इसी दौरान ये घटना हुई। मृतक जवान का नाम जालम सिंह नेताम है। उसकी उम्र 35 साल है। मूल रूप से बनियागांव का रहने वाला था और वर्तमान में दिल्ली में पदस्थ था। जालम सिंह 60 दिनों की छुट्टियों पर घर बनियागांव आया था। शनिवार सुबह अपने निर्माणाधीन नए घर में पानी डाल रहा था। इसी दौरान अचानक उसे चक्कर आ गया और वह बेहोश हो गया। परिजन तुरंत जालम सिंह को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जवान बेटे की अचानक मौत के बाद परिवार के लोग सदमे में हैं। डॉक्टर हार्ट अटैक की आशंका जता रहे हैं।

स्टार रेटिंग में अंबिकापुर को 3 स्टार रैंक, ओडीएफ++ बरकरार

सरगुजा। स्वच्छता सर्वेक्षण के परिणाम अब तक घोषित नहीं हुए हैं। लेकिन स्टार रेटिंग और ओडीएफ के परिणाम जारी हो चुके हैं। देश को स्वच्छता के कई मॉडल देने वाला अंबिकापुर इस बार स्टार रेटिंग में पिछड़ गया है। 5 स्टार से घटकर अंबिकापुर 3 स्टार शहरों में शुमार हो गया है। इसके साथ ही ओडीएफ ++ का तमगा अब भी बरकरार है। छत्तीसगढ़ में रायपुर नगर निगम और पाटन नगर पंचायत की रैंकिंग 5 स्टार है। राजनांदगांव, अंबिकापुर, बिलासपुर नगर निगम की रैंकिंग 3 स्टार है। अंबिकापुर को डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, कचरे का सेग्रीगेशन जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पूरे नम्बर मिले हैं, जिस वजह से 3 स्टार रेटिंग मिली है, लेकिन शहर के चौक चौराहों में ब्यूटीफिकेशन, सड़कों की जर्जर स्थिति के कारण इस बार नम्बर कटे और 5 स्टार का तमगा अंबिकापुर से छिन गया। ओडीएफ ++ में अंबिकापुर सफल रहा है। शहर में 28 हजार परिवार हैं जो टॉयलेट यूज कर रहे हैं। इसके अलावा सार्वजनिक शौचालयों की संख्या 36 है।

अंबिकापुर में ड्रोन से पहुंचेगी दवाइयां और सैंपल

सरगुजा। अंबिकापुर के राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का चयन ड्रोन टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर सेक्टर के लिए किया गया है। भारत सरकार ने देश के 25 मेडिकल कॉलेज का चयन इस टेक्नोलॉजी के लिए किया गया है जिसमें सरगुजा के मेडिकल कॉलेज का नाम भी शामिल है। ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग यातायात बाधित होने, आपदा विपदा के दौरान दवाओं, सैम्पल जमा करने के लिए किया जाएगा। पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तहत तीन महीने के लिए सीएचसी उदयपुर से मेडिकल कॉलेज तक इसका संचालन किया जाना है। इस ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए टीम को विशेष प्रशिक्षण के लिए दिल्ली भेजा जाएगा। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार लगातार नए नए प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में अब भारत सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए अत्याधुनिक ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी इसमें शामिल करने का निर्णय लिया है।

कबड्डी खेलो इंडिया सेंटर की मिली स्वीकृति

■ **सांसद संतोष पांडेय ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग का जताया आभार**

कवर्धा। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडेय की मांग और प्रयास पर केंद्रीय खेल मंत्रालय ने कबीरधाम जिले में खेलो इंडिया अंतर्गत कबड्डी खेलो इंडिया सेंटर खोलने की स्वीकृति दे दी है। सांसद संतोष पांडेय ने कबीरधाम जिले में खेलो इंडिया अंतर्गत कबड्डी, तिरंदाजी खेल को लेकर खेल अकादमी खोले जाने की मांग को लेकर दिल्ली में 23 जुलाई 2023 को केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से मुलाकात कर उन्हें इस संबंध में पत्र सौंपा था।

इससे पहले 25 दिसंबर 2022 को भी सांसद पांडेय ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निसीथ प्रमाणिक को इस संबंध में पत्र सौंपा था। सांसद ने केंद्रीय खेल मंत्री को लिखे पत्र और उनसे चर्चा के दौरान उन्हें बताया था कि खेल

के क्षेत्र में कबीरधाम जिले की अलग पहचान है। जिले में खेल प्रतिभा बहुत है। जिले के खिलाड़ी विभिन्न खेलों में दक्ष हैं और प्रदेश सहित राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं। कई उपलब्धियां भी हासिल किए हैं।

उन्होंने बताया था कि, जिले में लगातार खिलाड़ियों की संख्या बढ़ रही है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने, उचित मंच प्रदान करने और उनकी प्रतिभा को और निखारने के लिए कवर्धा में केंद्र सरकार की खेलो इंडिया योजना अंतर्गत कबड्डी और तिरंदाजी का खेल अकादमी खोले जाने की आवश्यकता है। इससे खिलाड़ियों को बहुत फायदा मिलेगा। इस दौरान केंद्रीय खेल मंत्री ने ठोस आश्वासन दिया था। इसके मद्देनजर उन्होंने कबीरधाम जिले में कबड्डी खेलो इंडिया सेंटर की स्वीकृति प्रदान कर जिलेवासियों को सौगात दी है।

सांसद पांडेय ने बताया कि खेल हमारे राष्ट्र के समग्र विकास के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में खेल के क्षेत्र में लगातार प्रगति की है। केंद्र सरकार खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। कबड्डी सेंटर खुल जाने से खिलाड़ियों को फायदा मिलेगा। उन्हें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। सांसद पांडेय ने जिले में कबड्डी सेंटर की स्वीकृति प्रदान करने के लिए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का आभार जताया है।

स्वस्थ्य शरीर से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण इसलिए खेल जरूरी: बृजमोहन

■ **भव्य रूप में मनाया जायेगा माता खल्लारी मेला**

बागबाहरा। वरिष्ठ मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल शुक्रवार को बागबाहरा में आयोजित अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने खिलाडियों का हौसला बढ़ते हुए कहा कि खेल और खिलाडियों का समाज से गहरा नाता होता है। खेल शारीरिक के साथ मानसिक तौर पर भी मजबूती प्रदान करते हैं। खेलों का राष्ट्र निर्माण में भी बहुत बड़ा योगदान होता है।

उन्होंने कहा कि खेलों के जरिए खिलाड़ी जीवन में संघर्ष, आत्मविश्वास, समर्पण सीखता है। पहले के समय कहा जाता था की पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन अब यह भ्रांति टूट चुकी है। आज खिलाड़ी अपने हुनर से देश का नाम रौशन कर रहे है। खेलों के जरिए समाज मे सम्मान के साथ ही रोजगार पा रहे हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने खेलों में एक अलग ही स्थान हासिल किया है। ओलंपिक से लेकर कॉमनवेल्थ गेमों तक में भारत ने अपना झंडा गाड़ा है। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा सरकार ने हमेशा खेल और खिलाडियों को प्रोत्साहन देने का काम किया है उसके लिए उचित प्रशिक्षण और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काफी काम किया गया। पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान राज्य में खेल और खिलाडियों की उपेक्षा हुई। लेकिन अब फिर से छत्तीसगढ़ को खेलों में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने की हर संभव कोशिश होगी। उसके लिए जरूरी प्रशिक्षण और इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की जाएगी। इस मौके पर मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने माता खल्लारी मेला को भव्य रूप प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए राशि देने की घोषणा की। प्रतियोगिता का आयोजन मेघ खेल एवं नवयुवक मंडल ने किया था। जिसमे देश भर से महिला और पुरुष कबड्डी खिलाड़ी हिस्सा ले रहे है। कार्यक्रम में सांसद श्री चुन्नी लाल साहू विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा, पूर्व विधायक श्रीमती अल्का चंद्राकर, नरेश चंद्राकर, मेघ खेल एवं युवा संगठन आयोजन समिति के संयोजक डेमन राज पनुरिया, अध्यक्ष भोजनाथ कल्लू देवांगन, सचिव देवेश साहू समेत बड़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित रहे।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा से की मुलाकात

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार को नवा रायपुर, अटल नगर स्थित न्यू सर्किट हाउस में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी उपस्थित थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्ति से पहले जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा इलाहाबाद हाईकोर्ट में नियुक्त थे। उन्होंने सन् 1990 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री ली। इसके बाद 8 सितंबर 1990 को अधिवक्ता के रूप में नामांकन करवा वकालत की शुरुआत की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए उन्हें क्रिमिनल व सिविल मैटर में दक्षता हासिल हुई। 21 सालों की वकालत के बाद बार कोटे से 21 नवंबर 2011 को वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदस्थ हुए। लगभग 2 साल बाद 6 अगस्त 2013 को उन्होंने स्थायी न्यायाधीश के रूप में इलाहाबाद हाईकोर्ट में काम शुरू किया। वे प्रशासनिक आयोग लखनऊ के सदस्य पद पर भी रहे हैं। उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 4 सितंबर 2026 है।

अन्याय के विरुद्ध न्याय की इस लड़ाई में हम फिर आ रहे : दीपक बैज

रायपुर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने ट्वीटर पर यात्रा को लेकर वीडियो शेयर किया है। उन्होंने लिखा है, अन्याय के विरुद्ध न्याय की इस लड़ाई में हम फिर आ रहे हैं। करोड़ों देशवासियों की मोहब्बत और दुआएं साथ लेकर तानाशाही और अहंकार को करारा जवाब देने फिर यात्रा निकाली जा रही। बैज ने कहा, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाइए, इस न्याय यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। न्याय की यह यात्रा जारी है, न्याय का हक मिलने तक जारी रहेगी।

पहली बार 5 स्टार रैंकिंग में पहुंचा रायपुर पालिका, राष्ट्रपति के हाथों मिलेगा अवार्ड

रायपुर। नगर पालिका निगम रायपुर अब तीन स्टार से 5 स्टार में पहुंच गया है। महापौर एजाज ढेबर ने बताया, राष्ट्रपति के हाथों में रायपुर पालिका को तीन अलग-अलग अवार्ड मिलेगा। नगरीय निकाय रैंकिंग में रायपुर को तीन अवार्ड मिलेगा। महापौर ढेबर ने बताया, रायपुर को वॉटर प्लस अवार्ड मिलेगा। ओडीएफ ++ अवार्ड मिलेगा। देश के 4000 नगरीय निकायों के बीच सर्वेक्षण होता है। पहली बार 5 स्टार रैंकिंग में रायपुर नगर पालिका निगम पहुंचा है।

शिक्षा मंत्री ने 40वीं एनटीपीसी राष्ट्रीय सब जूनियर तीरंदाजी स्पर्धा का किया शुभारंभ

रायपुर। शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर स्थित साइंस कॉलेज मैदान में छत्तीसगढ़ प्रदेश आर्चरी एसोसिएशन की ओर से आयोजित 40वीं एनटीपीसी राष्ट्रीय सब जूनियर का प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। इस प्रतियोगिता में देश के सभी राज्यों से लगभग एक हजार खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेल और खिलाड़ियों के एक बार फिर से अच्छे दिन आने वाले हैं। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान मिलेगी। छत्तीसगढ़ तीरंदाजी संघ ने पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया है। राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने राज्य में खेलों के विकास के लिए हर संभव मदद की बात कही। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि राज्य में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा, जिससे वे खेलों में छत्तीसगढ़ का नाम रौशन कर सकें।

राज्यपाल ने आदित्य एल-1 की उपलब्धि पर वैज्ञानिकों को दी बधाई

रायपुर। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य-एल 1 के अपनी कक्षा तक पहुँचने पर वैज्ञानिकों सहित देशवासियों को बधाई दी है। राज्यपाल ने अपने सन्देश में कहा कि यह उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का परिणाम है। यह सफलता विकसित भारत की प्रतिभा को भी प्रदर्शित कर रही है। इसके बाद भारत, सूर्य का अध्ययन करने वाले दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल हो गया है।

15 लाख से अधिक मतदाता लोकसभा चुनाव के लिए बढ़े हैं

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विगत पांच वर्षों में 15 लाख से अधिक मतदाता लोकसभा चुनाव के लिए बढ़े हैं। इसमें 67,2685 पुरुष, 83,3,656 महिला और 30 तीसरे लिंग के शामिल हैं। प्रदेश में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या बढ़ी है। मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन के तहत छह जनवरी 2024 की स्थिति में कुल 2,04,22,656 पंजीकृत मतदाता हैं। इसमें पुरुषों की संख्या 1,01,49,798, महिलाओं की 1,02,72,119 और थर्ड जेंडर 739 हैं। मतदाता सूची में दिव्यांग चिन्हांकित मतदाताओं की संख्या प्रारंभिक प्रकाशन में 1,62,215 है। 1 जनवरी की स्थिति में 18-19 आयुवर्ग समूह के कुल मतदाताओं की संख्या 4,94,452 है। वरिष्ठ नागरिक मतदाता (80 आयु वर्ग) 2,22,533 है।

संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह, सीएम विष्णुदेव साय ने कहा-

व्यर्थ नहीं जाएगा कार्यकर्ताओं का बलिदान मोदी की हर गारंटी करेंगे पूरी : मुख्यमंत्री

जगदलपुर। धरमपुरा के पीएमटी मैदान में आयोजित संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा, चुनाव के दौरान और चुनाव के पहले भी हमारे पार्टी के कई अच्छे-अच्छे कार्यकर्ता नक्सलवाद के शिकार हुए। उन सभी को मैं नमन करता हूं। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। बस्तर के लोगों का स्वागत है। आपने 12 में से 8 सीटें जिताकर दी है।

सीएम साय ने कहा, पहली बार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं और आज एक आदिवासी मुख्यमंत्री का बस्तर में पहली बार आप लोगों के बीच में आगमन हुआ है। हमारे नेता बता रहे थे कि आज हमारे सरकार को बने हुए 24 -25 दिन हो गए हैं, लेकिन 24 ङ्क 25 दिन में हमने कई बड़े-बड़े कार्य संपन्न किए हैं, जो मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने जो वादा किया था उसे पूरा किया है। शपथ लेने के दूसरे दिन 18 लाख गरीब लोगों पर प्रधानमंत्री आवास दिए जाने का निर्णय लिया गया है। कांग्रेस की सरकार में एक भी प्रधानमंत्री आवास का काम नहीं हुआ। हमारे गरीबों का हक छीना गया।

सीएम ने कहा, हमारी पार्टी का वादा था कि सरकार और मुख्यमंत्री होगा वह पहले काम 18 लाख गरीबों को पक्का मकान स्वीकृत करेगा और 13 दिसंबर को सरकार ने शपथ ली। 15 दिसंबर को यह वादा पूरा किया। 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए, लेकिन आपको बताते हुए मुझे गौरव होता है कि 25 दिसंबर को हमारे छत्तीसगढ़ में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई का सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूरे प्रदेश में जगह-जगह कार्यक्रम करके करोड़ रुपए से ज्यादा बोनस की राशि खाते में दी गई है। यह काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है।

विष्णुदेव साय ने कहा, आज छत्तीसगढ़ में हमारे युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ था। पीएससी में बहुत घोटाला हुआ था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो जांच करेंगे और आप लोगों को बताते हुए मुझे खुशी होती है कि हमने अभी घोटाले की जांच के लिए सीबीआई को सौंपा है। उनमें से कोई नहीं बचेगा, सब के ऊपर कार्यवाही होगी। मोदी की गारंटी में जो-जो वादे किए गए हैं वह सभी आने वाले 5 साल में हमें पूरे करने हैं।

सीएम ने कहा, आज महतारी वंदन योजना और विवाहित महिला को साल में 12000 दिए जाने का हमारा वादा है। साल में 12000 महतारी वंदन योजना में आएगा। तेंदूपत्ता जिसे हम लोग हरा सोना कहते हैं, ट्राइबल लोगों के आय का ज़रिया है। आज प्रति मानक बोरा 5?30 हजार रुपए दिए जाने का वादा है, उसे पूरा करेंगे और बोनस भी दिया जाएगा। जो भी भूमिहीन किसान मजदूर हैं उन्हें सरकार साल में ?10000 देने का कार्य करेगी। पद खाली है उन्हें पूरी प्रदेश के साथ हमारे सरकार भरने का काम करेगी। आप सभी को मालूम है कि मोदी की गारंटी में हमारी सरकार ने क्या-क्या बातें किए हैं और ज्यादा बताने समय नहीं है। हमें दूसरे संभाग के कार्यक्रम में भी जाना है। मैं मुख्यमंत्री के नाते कह सकता हूं कि मोदी की गारंटी को पूरा करेंगे।

मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जगदलपुर पहुंचने पर सीएम साय का जोरदार स्वागत

जगदलपुर। जगदलपुर के मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के बस्तर अंचल में प्रथम आगमन पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री साय के साथ उप-मुख्यमंत्री अरुण साव एवं रामप्रताप सिंह भी जगदलपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सीएम विष्णुदेव साय जगदलपुर पहुंचे हैं। यहां वे संभागस्तरीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह में शामिल हुए, यहां वे बस्तर संभाग के सभी सात जिलों के भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करेंगे और आगामी चुनाव में किस तरह से कार्य करना है और केन्द्र की भाजपा सरकार की उपलब्धियां आम जनमानस तक कैसे पहुंचाना है इसके बारे में बताएंगे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री साय का प्रथम बस्तर प्रवास है। जिसको देखते हुये भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री के आगमन पर एयरपोर्ट से लेकर सभास्थल तक जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने जोश भरे नारों और पुष्प गुच्छ के साथ अपने नये मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान बाइक रैली भी निकाली गई जो मुख्यमंत्री के गाड़ी सामने चलती रही। इस दौरान एयरपोर्ट में कोंडागांव विधायक लता उसेंडी, जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, पूर्व विधायक संतोष बाफना, बैदूराम कश्यप, सुभाऊ कश्यप, राजाराम तोड़ेम के साथ-साथ बस्तर संभागायुक्त श्याम धावड़े, आईजी सुंदरराज पी., कलेक्टर विजय दयाराम के., एसएसपी जितेन्द्र मीणा, मुख्य वन संरक्षक द्वय गुप्ता, सीईओ जिला पंचायत प्रकाश सर्वे, सहित अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने पहले जगदलपुर प्रवास पर हैं। सीएम की सुरक्षा की व्यवस्था पुलिस और प्रशासन ने की हुई है, उनके कार्यक्रम में किसी प्रकार की खलल ना उत्पन्न हो इस लिए पुलिस ने कांग्रेस के कई कार्यकताओं और नेताओं को नजरबंद कर दिया है।

नक्सलियों के लिए मुख्यधारा में लौटने के रास्ते खुले हैं: विजय शर्मा

दंतेवाड़ा। भाजपा सरकार बनने के बाद पहली बार नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा दंतेश्वरी माता के दर्शन के लिए दंतेवाड़ा पहुंचे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी ओममाथुर, वन मंत्री केदार कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा व विधायक किरण सिंह देव के साथ दंतेवाड़ा विधायक चैतराम आटामी मौजूद रहे। इस दौरान दर्शन के लिए मंदिर में लाइन में खड़े लोगों का अभिवादन कर उपमुख्यमंत्री शर्मा ने दर्शन करने वाले भक्तों को नहीं रोकने कहा।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शनिवार सुबह कारली हैलीपेड पहुंचे, वहां से सीधे दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे। यहां दर्शन करने के बाद डिप्टी सीएम जगदलपुर के लिए रवाना हो गए। इस दौरान हेलीपेड से लेकर दंतेश्वरी मंदिर के बीच बड़ी संख्या में स्थानीय भाजपा नेता और समर्थक डिप्टी सीएम के स्वागत के लिए मौजूद रहे। इस दौरान नक्सलवाद को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलियों के लिए मुख्यधारा में लौटने के रास्ते खुले हैं। नक्सलियों से जुड़े लोगों से अपील है कि वे मुख्यधारा में लौट आएं। उन्होने कहा कि अभी हाल ही में नक्सलियों के आईईडी विस्फोट में तीन जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, यह बहुत ही पीड़ा दायक है, मैं घायल जवानों से मिलने अस्पताल गया था, मुझे बहुत तकलीफ हुई। जवानों के साथ-साथ उनके परिवारों को ऐसी घटनाओं से बहुत पीड़ा होती है।

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि भाजपा की लो प्रोफाइल सरकार आपको मिलेगी। सरकार बने 25 दिन में हमने अहम फैसले लिए हैं। नौजवानों के परिश्रम को पीएससी के माध्यम से धूल में मिलाया गया था, उस पर हमने सीबीआई जांच के आदेश दिये हैं। उन्होने कहा कि सरकार सभी घोषणाओं को पूरा करेगी। बीमार और मृतक को कांवड़ में ढोने के सवाल पर उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि अभी सरकार बनी है। दुबारा ऐसी स्थिति निर्मित न हो ऐसा पूरा प्रयास करेंगे।

मंत्री की नाराजगी खाद्य अधिकारी को पड़ी भारी

रायपुर। वरिष्ठ सहायक खाद्य अधिकारी के होते हुए भी कनिष्ठ सहायक खाद्य अधिकारियों को प्रभारी बनाने वाले रायपुर के खाद्य अधिकारी छुट्टी कर दी गई है। समीक्षा बैठक के दौरान इस नियुक्ति पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल गहरी आपत्ति जताई थी।

गौरतलब है कि 4 जनवरी को खाद्य मंत्री दयालदास विभाग ने अपने विभाग की समीक्षा बैठक ली थी। बैठक के दौरान उन्होंने प्रदेश के कई जिलों में वरिष्ठ सहायक खाद्य अधिकारी की पदस्थापना के बाद भी विभाग का प्रभार कनिष्ठ सहायक खाद्य अधिकारियों के पास होने की बात पर गहरी नाराजगी जतायी थी। बैठक के दौरान मंत्री ने तत्काल ऐसे जिला में वरिष्ठ सहायक खाद्य अधिकारियों को खाद्य नियंत्रक की जवाबदारी सौंपने का आदेश दिया गया था।

ईडी की चार्जशीट राजनीतिक षड़यंत्र का हिस्सा: भूपेश

ईडी अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर गिरफ्तार कर रही

रायपुर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जिस तरह से उनका नाम लिखा है, वह पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। उन्होंने कहा है कि ईडी अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर कूटरचना कर लोगों को गिरफ्तार कर रही है और उनसे दबावपूर्वक मेरे और मेरे सहयोगियों के खिलाफ बयान दिलवा रही है। उन्होंने कहा है कि इन बयानों में जो पैसों के लेनदेन के आरोप लगाए गए हैं उनका कोई आधार नहीं है।

बघेल ने कहा है कि जिस असीम दास के पास से रुपए बरामद हुए थे उसने जेल से अपने हस्तलिखित बयान में कह दिया है कि उन्हें भी धोखे में रखकर फंसाया गया है और उन्होंने कभी किसी राजनेता व उनसे जुड़े लोगों को पैसा नहीं पहुंचाया। अब ईडी दावा कर रही है कि उसने यह बयान भी वापस ले लिया है। यह किस दबाव में हो रहा है, उसे सब जानते हैं। उन्होंने सवाल पूछा है कि ईडी ने जिस दिन कथित रूप से असीम दास से रुपए बरामद किए थे उस घटना की पूरी रिकॉर्डिंग ईडी के पास है। इसका मतलब है कि पूरी घटना पूर्व नियोजित थी और इसका मतलब यही है कि इसकी कूटरचना ईडी ने ही की थी।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि ईडी ने दावा किया है कि चंद्रभूषण वर्मा ने भी अपना पहले का बयान वापस ले लिया है। श्री बघेल ने कहा है कि हम शुरुआत से कह रहे हैं कि ईडी मारपीट से लेकर धमकी देने तक हर हथकंडे अपनाकर मेरा व मेरे सहयोगियों का नाम लेने का दबाव बना रही है। ईडी के नए दस्तावेज से यह और स्पष्ट हो गया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि महादेव ऐप के घोटाले की जाँच उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए खुद शुरू की थी। वे चाहते थे कि इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ हो और युवाओं को जुआखोरी की ओर धकेल रहे इस अपराध पर रोक लगे।

छत्तीसगढ़ सरकार की इस जाँच के आधार पर ही ईडी धन-शोधन का मामला बनाकर जाँच कर रही है लेकिन दुर्भाग्य है कि ईडी ने जाँच को अपराध की बजाय राजनीतिक दबाव व बदनामी का हथियार बना लिया है। उन्होंने कहा है कि महादेव ऐप के पूरे मामले को जिस तरह से राजनीतिक रंग दिया गया है उससे साफ है कि इसका उद्देश्य अब असली अपराधियों को बचाने और राजनीतिक दुष्प्रचार कर भाजपा को फायदा पहुँचाने का ही रह गया है।

हसदेव जंगल में पेड़ों की कटाई के विरोध में आज मार्च

रायपुर। हसदेव में पेड़ों की कटाई और आदिवासियों के दमन के खिलाफ 7 जनवरी को जनवादी संगठन मार्च निकाल रहे हैं। इस मार्च के जरिए हसदेव में पेड़ों की कटाई का विरोध किया जाएगा। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन और छत्तीसगढ़ किसान सभा के प्रमुखों ने रायपुर प्रेस क्लब में ये जानकारी दी।

हसदेव में पेड़ों की कटाई के विरोध में नागरिक प्रतिरोध मार्च 7 जनवरी को सिलतरा से हरिहरपुर तक होगा। जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी जनवादी संगठन और किसान संगठनों के नेता भी शामिल होंगे। संगठनों ने फर्जी ग्राम सभा के माध्यम से हसदेव में पेड़ों की कटाई करने का आरोप शासन प्रशासन पर लगाया। साथ ही कहा कि आदिवासी और सरपंचों के साथ अमानवीय कृत्य करने के साथ ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। हसदेव जंगल की कटाई कारपोरेट जगत को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कर रही है।

छत्तीसगढ़ किसान सभा के संरक्षक संजय पराते ने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के तुरंत बाद ही हसदेव के जंगलों की कटाई शुरू की गई है। सरकार संविधान की रक्षा करने की शपथ लेकर आई है लेकिन आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार और इस देश में आदिवासियों के लिए जो कानून बने हैं उनकी रक्षा का भी सवाल है। हसदेव

के जंगल कटाई में आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार और कानून का उल्लंघन हुआ है। आदिवासियों के पेशा कानून और अधिकार सर्वोच्च स्थान रखता है। फर्जी ग्राम सभाओं के माध्यम से हसदेव के जंगल की कटाई की जा रही है, जो गलत और गैरकानूनी है। हसदेव का जंगल आदिवासियों के अस्तित्व के साथ ही कई मायनों में महत्वपूर्ण है।

हसदेव जंगल की कटाई का विरोध

छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के प्रमुख आलोक शुक्ला का कहना है कि हसदेव का जंगल पूरे मध्य भारत के लिए महत्वपूर्ण है जो छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहलाता है। हसदेव के जंगल को बचाने की अनुशंसा छत्तीसगढ़ विधानसभा और भारतीय वन्यजीव संस्थान ने की है। बावजूद इसके संवैधानिक ग्राम सभाओं की अवहेलना करके हसदेव के जंगल को काटा जा रहा है। आदिवासियों के विरोध को दरकिनार करके कॉरपोरेट जगत को फायदा पहुंचाने के लिए हसदेव के जंगल को काटा जा रहा है। 21, 22 और 23 दिसंबर को फोर्स लगाकर हसदेव के जंगल को काटा गया। आदिवासी और सरपंचों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। इसके विरोध में छत्तीसगढ़ के जनवादी संगठन राजनीतिक दल के लोग और विभिन्न किसान संगठनों के द्वारा 7 जनवरी को नागरिक प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों से लगभग हजारों की तादाद में लोग हसदेव पहुंचकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। हसदेव के जंगल की कटाई को लेकर छत्तीसगढ़ ही नहीं नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के साथ ही पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है।

महादेव सट्टा एप पर भाजपा ने ईडी को सौंपे अहम दस्तावेज, जांच की मांग

रायपुर। महादेव सट्टा एप के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दस्तावेज सौंपा है। भाजपा विधायक राजेश मूणत ने ईडी को दस्तावेज दिए जाने की जानकारी देते हुए कहा कि अरबों-खरबों की इस लेन-देन पर दुर्ग (पुलिस) से जानकारी भी मांगी थी, इस पर हमने अपनी ओर से कुछ दस्तावेज ईडी को दिए हैं, और कहा कि इस पर भी जांच की जाए।

भाजपा ने ऐसे समय में दस्तावेज ईडी को सौंपा है, जब कांग्रेस की ओर से ईडी को जांच एजेंसी नहीं बीजेपी की षड्यंत्रकारी एजेंसी करार दिया है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने एक वीडियो जारी कर कहा कि असीम दास के आरोपों पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ प्रेसनोट जारी किया गया था। इसके बाद असीम दास ने

कोर्ट में अपने बयान में इसका खंडन भी किया है।

उन्होंने कहा कि अब असीम दास का बयान झूठलाने के लिए ईडी जेल अंदर जाकर उसका बयान ले रही है। ऐसे में थर्ड डिग्री वाले बयान या कोर्ट के बयान, किसे ऑथेंटिक माना जाए। सभी बयानों से साफ होता है, यह ईडी का षड्यंत्र है। पूरी तरीके से इसका मुकाबला किया जाएगा। भूपेश बघेल पाक साफ होकर निकलेंगे और भाजपा का षड्यंत्र सबके सामने होगा। वहीं, पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हुए हमले को लेकर सुशील आनंद ने कहा कि क्रिया की प्रतिक्रिया भी आने लगी है।

दरअसल, महादेव सट्टा एप मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में 5 नए लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें शुभम सोनी, अनिल अग्रवाल, रोहित गुलाटी, भीम सिंह और असीम दास है। चार्जशीट में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के नाम का भी जिक्र है। शुभम सोनी के बयान में भूपेश बघेल पर लगाए आरोपों के कारण उनका नाम सामने आया है। शुभम सोनी ने भूपेश पर 508 करोड़ लेने का आरोप लगाया था।

कोल लेवी और मनी लांड्रिंग मामले में विशेष न्यायालय में सुनवाई

रायपुर। कोल लेवी वसूली और मनी लांड्रिंग मामले में ईडी और आरोपियों के आवेदनों पर विशेष न्यायालय में शनिवार को सुनवाई शुरू हुई। हाई प्रोफाइल केस की वजह से जिला कोर्ट परिसर में हलचल देखी जा रही है। जानकारी के अनुसार, ईडी की ओर से जहां मामले के आरोपियों से जेल में पूछताछ की अनुमति के लिए याचिका लगाई गई है। वहीं दूसरी ओर आरोपियों में निलंबित आईएएस रानू साहू और पूर्व सीएम की उप सचिव सौम्या चौरसिया की ओर से स्वास्थ्यगत कारणों से पेश होने से छूट मांगी है। इसके अलावा कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की से दायर अग्रिम जमानत याचिका के साथ कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ ईडी की ओर से गैर जमानती वारंट जारी करने की याचिका पर सुनवाई होगी। बताया जा रहा है कि देवेंद्र यादव के साथ राम गोपाल अग्रवाल दोनों की कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। देवेंद्र यादव के दिल्ली में होने की खबर है, वहीं अग्रवाल के देश से बाहर होने की बात कही जा रही है। रामगोपाल अग्रवाल अब तक ईडी की ओर से जारी चार समन के बाद भी पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं। बीते साल सितंबर और अक्टूबर माह में समन जारी किए गए थे। उन्हें पेश करने के लिए हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी रायपुर पुलिस ने मदद नहीं की थी।

मालदीव के मन में क्या है ? तोड़ा पीएम मोदी से समझौता

अभिनय आकाश

इस वक्त भारत और मालदीव के रिश्तों में कुछ न कुछ कड़वाहट देखी जा रही है। दरअसल, 2018 ये वो साल था जब भारत और मालदीव के संबंध सबसे ज्यादा बेहतर होने की शुरुआत हुई थी। उस वक्त वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद सालेह थे। मोहम्मद सालेह के बारे में कहा जाता है कि वो इंडिया फस्ट नीति पर काम करते थे। भारत पर यकीन करते थे। भारत से हर तरह के सौदे करते थे। उस वक्त मालदीव के साथ भारत के संबंध बहुत मजबूत थे। लेकिन इस साल हुए चुनाव में उनकी सत्ता चली गई। उसके बाद से ही ये सवाल उठने लगा था कि भारत और मालदीव के संबंधों में खटास होगी। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोइज्जु भारत को इतना ज्यादा पसंद नहीं करते। उनके भारत विरोधी बयान भी कई बार सामने आ चुके हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत सरकार से देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस लेने का औपचारिक अनुरोध किया। अब भारत को मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने के लिए कहने के बमुश्किल एक महीने बाद, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की सरकार ने हाइड्रोग्राफिक पर भारत के साथ पिछली सरकार के समझौते को नवीनीकृत नहीं करने का फैसला किया है। मुइज्जू ने इस साल अक्टूबर में राष्ट्रपति चुनाव जीता और उनकी जीत देश में विदेशी शक्तियों की भूमिका को लेकर चल रही बड़ी बहस के बीच हुई है। मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक छोटा द्वीप देश है, और लगभग 500,000 लोगों का घर है। करीब एक दशक से चीन उसके साथ संबंध प्रगाढ़ करने का प्रयास कर रहा है। यह अवधि दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहित चीन के उदय और उसकी शक्ति के प्रक्षेपण के साथ मेल खाती है। लंबे समय से भारत मालदीव को अपने क्षेत्रीय प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा मानता रहा है। मालदीव के ताकतवर पूर्व राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम ने कई वर्षों तक भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे। 2008 के चुनावों में उनकी हार के साथ, नए नेताओं के चुनाव अभियान में विदेश नीति एक महत्वपूर्ण तत्व बन गई है। 2008 में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) के मोहम्मद नशीद ने जीत हासिल की। एमडीपी और उसके शीर्ष नेताओं, विशेषकर नशीद को भारत समर्थक के रूप में देखा जाता था। जब अब्दुल्ला यामीन 2013 और 2018 के बीच राष्ट्रपति रहे तो भारत और मालदीव के बीच संबंध काफी खराब हो गए। 2018 में सोलिह के सत्ता में आने के बाद ही नई दिल्ली और माले के बीच संबंधों में सुधार हुआ। सोलिह लगातार भारत के साथ संबंधों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और इंडिया फर्स्ट नीति पर चल रहे थे। अपने चुनाव के बाद मुइज्जू ने कहा था कि उनके हिंद महासागर द्वीपसमूह देश में मौजूद सभी भारतीय सैन्यकर्मियों को बाहर निकालना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। 8 जून, 2019 को हस्ताक्षरित समझौता, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के निमंत्रण पर मालदीव का दौरा किया। भारत को मालदीव के क्षेत्रीय जल, अध्ययन और चार्ट रीफ, लैगून, समुद्र तट, महासागर का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी। यह पहला द्विपक्षीय समझौता है जिसे नवनिर्वाचित मालदीव सरकार, जिसने नवंबर में कार्यभार संभाला था, आधिकारिक तौर पर समाप्त कर रही है। एक संवाददाता सम्मेलन में मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय में सार्वजनिक नीति के अवर सचिव मोहम्मद फ़िरुज़ुल अब्दुल खलील ने कहा कि मुइज़ू सरकार ने 7 जून, 2024 को समाप्त होने वाले हाइड्रोग्राफी समझौते को नवीनीकृत नहीं करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस समझौते की शर्तों के अनुसार, यदि एक पक्ष समझौते को छोड़ना चाहता है, तो समझौते की समाप्ति से छह महीने पहले दूसरे पक्ष को निर्णय के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। शर्तों के अनुसार, समझौता स्वचालित रूप से अतिरिक्त पांच वर्षों के लिए नवीनीकृत हो जाता है। फ़िरोज़ुल ने कहा कि भारत को सूचित किया गया है कि मालदीव समझौते पर आगे नहीं बढ़ना चाहता है। माले के सूत्रों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मालदीव सरकार ने मुइज़ू प्रशासन के फैसले से वहां भारतीय उच्चायोग को अवगत करा दिया है।

जन आंदोलनों से निकले राजनीतिक दल

संजय तिवारी

स्वतंत्रता के बाद बीते 75 सालों में भारत ने तीन बड़े राजनीतिक आंदोलन देखे हैं। पहला, जेपी आंदोलन दूसरा, वीपी आंदोलन और तीसरा अन्ना आंदोलन। जेपी आंदोलन को छोड़ दें तो वीपी सिंह का आंदोलन और अन्ना आंदोलन कांग्रेस के भ्रष्टाचार के ही खिलाफ थे।

इन तीनों ही आंदोलनों की समय समय पर समीक्षा होती रहती है और आगे भी होती रहेगी। लेकिन एक सवाल का जवाब कभी नहीं मिलता कि इन आंदोलनों से निकले दल और नेता कालांतर में उन्हीं आरोपों से क्यों घिर गये जिनको मुद्दा बनाकर आंदोलन किया था? जय प्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ जनता को एकजुट किया था। इसलिए उनके पीछे जो जन आंदोलन खड़ा हुआ उसका मुद्दा सरकारी भ्रष्टाचार ही नहीं बल्कि इंदिरा गांधी की लोकतंत्र विरोधी तानाशाही भी थी।

लेकिन वीपी सिंह ने तो कांग्रेस से विद्रोह ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किया था। 1989 में लोकसभा चुनाव से पहले जो जनता दल बना था उसमें जनमोर्चा, जनता पार्टी, कांग्रेस (एस) और लोकदल समाहित हो गये थे। वो सब राजीव गांधी के खिलाफ एक सशक्त आवाज उठाना चाहते थे जिसमें नेहरु-गांधी परिवार द्वारा बोफोर्स में ली गयी दलाली को मुद्दा बनाया गया था।

वीपी सिंह की इमेज एक स्वच्छ राजनेता की थी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री और केन्द्र में वित्त मंत्री रहते हुए उन्होने अपनी मिस्टर क्लीन की छवि बनायी थी। शायद इसीलिए इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी ने उन्हें हमेशा भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे रहनेवाले रक्षा मंत्रालय का जिम्मा दे दिया। लेकिन रक्षामंत्री बनते ही उन्होंने बोफोर्स तोपों की खरीद की आंतरिक जांच शुरु करवा दी जिसका नतीजा ये हुआ कि तीन महीने के भीतर ही उन्हें रक्षामंत्री के पद से हटा दिया गया।

1989 के लोकसभा चुनाव में बोफोर्स ही बड़ा मुद्दा बना और राजीव गांधी की कांग्रेस चुनाव हार गयी। केन्द्र में वीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी। जिस जोश और जज्बे से कई सोशलिस्ट दलों को मिलाकर जनता दल बना था, वह जोश और जज्बा इतना हावी रहा कि दो साल के भीतर सरकार भी गयी और जनता दल भी बिखरने लगा। इस बिखराव से कई छोटे छोटे दल निकले जो आगे चलकर यूपी, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक के क्षेत्रीय क्षत्रप बने। लेकिन वीपी सिंह बुरी तरह असफल हुए। उन्होंने संभवतः मान लिया कि सरकार में बैठकर भ्रष्टाचार के दाग से बचना मुश्किल है इसलिए दूसरी बार जब 1996 में संयुक्त दलों द्वारा उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का प्रयास हुआ तो मना करके वो कुछ घण्टों के लिए घर छोड़कर ही चले गये।

अपने पहले कार्यकाल में ही सरकार चलाने का इतना कड़वा अनुभव उन्हें हो गया था कि दूसरी बार सबके कहने के बावजूद वो प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं हुए। प्रधानमंत्री बनने के बजाय बीमारी से घिर चुके वीपी सिंह ने कविता लिखने और पेन्टिन्ग बनाने को अपने लिए ज्यादा सुगम रास्ता समझा और बाकी के जीवन में इसी काम में व्यस्त रहे। उनकी जगह 1996 में देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने और उस सरकार का क्या हुआ यह सबने देखा था।

नब्बे के दशक के भीषण राजनीतिक उथल पुथल के बाद इक्कीसवीं सदी की शुरुआत अपेक्षाकृत स्थायित्व लिए हुई थी। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना कार्यकाल पूरा किया था और एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में लौट आयी। इस बार सोनिया गांधी ने सूझ बूझ से मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया क्योंकि उन पर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं था। लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार के कई संगीन आरोपों से घिर गयी। इसमें कोल स्कैम, टूजी स्कैम और कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला प्रमुख थे।

इन्हीं आंदोलनों की पृष्ठभूमि में 2011 में अन्ना आंदोलन का जन्म हुआ जो दो साल चलता रहा। इस आंदोलन से भी एक राजनीतिक पार्टी का जन्म हुआ जिसका नाम आम आदमी पार्टी है। जिन दिनों जंतर मंतर पर आंदोलन अपने चरम पर था उस समय कांग्रेस के नेता बार बार आंदोलनकारियों को चुनौती देते थे कि बाहर बैठकर भ्रष्टाचार की शिकायत करना आसान है, एक बार सिस्टम में बैठकर देखो तब समझ में आयेगा कि सरकार चलाना कितना कठिन काम है। कांग्रेस के नेता आंदोलनकारियों को अपना राजनीतिक दल बनाने की सलाह भी देते थे।

जब राजनीतिक दल बनाने की बात आयी तब आंदोलनकारियों में ही मतभेद हो गया। एक गुट चाहता था कि आंदोलनों की परिणिति राजनीतिक दल के रूप में नहीं होनी चाहिए। जबकि दूसरा गुट इसके पक्ष में था। जो गुट इसका विरोध कर रहा था उसमें ज्यादातर वो लोग थे जो जेपी आंदोलन और वीपी आंदोलन से निकले दलों का हाल देख चुके थे। खुद अन्ना हजारे भी इसके समर्थन में नहीं थे। लेकिन दल बना और उस दल की दो राज्यों में सरकार भी बनी।

आज वह दल उसी तरह के भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा हुआ है जिस तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में उसका जन्म हुआ था। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह लेकिन मूल सवाल तो यही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलनों से निकले राजनीतिक दल ही भ्रष्टाचार के आरोपों से क्यों घिर जाते हैं? क्या राजनीति और सत्ता तंत्र की मजबूरी है कि बिना भ्रष्टाचार के वो सरकार चला ही नहीं सकते?

कुछ हद तक इसका उत्तर है, हां। हमारी राजनीतिक व्यवस्था ऐसी बनती गयी है जिसमें भ्रष्टाचार उसका अनिवार्य हिस्सा हो गया है। जिन दिनों जंतर मंतर पर भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना आंदोलन चल रहा था, उन दिनों वकील और डॉक्टर भी भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना समर्थन देने आते थे। वो क्यों आते थे भला? उन पर तो खुद ग्राहकों से लूटपाट और भ्रष्ट आचरण का आरोप लगता रहता है तो फिर वो किस भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होना चाहते थे?

इसका जवाब इतना सरल नहीं है कि एक समूह या वर्ग को भ्रष्ट बताकर हम बाकी सबको क्लीन चिट दे दें। राजनीति अब एक मंहगा सौदा है। चुनाव आयोग चाहे जितनी निगरानी करे एक उम्मीदवार का चुनाव लड़ने का खर्चा करोड़ों में होता है। इसके अलावा जनता के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए भी उसे नियमित बड़ी रकम खर्च करनी होती है ताकि वह लोगों की मदद करके उनके बीच अपनी विश्वसनीयता बना सके। जनता भी नेता से यही उम्मीद करती है कि अगर वह आया है तो कुछ देकर जाए। फिर अगर अगला चुनाव जीतना है तो जनता के सौ उल्टे सीधे काम उसे करने पड़ते हैं, वह चाहे या न चाहे। अगर कोई ईमानदारी का बैनर लटका लेगा तो सबसे पहले उसका समर्थक वर्ग ही उससे नाराज हो जाएगा।

जब अर्थव्यवस्था पूंजीवादी हुई है तो समाज व्यवस्था वैराग्यवादी कैसे हो जाएगी? इसलिए नौकरशाह अगर अपना घर भरने के लिए भ्रष्टाचार करता है तो नेता अपनी राजनीति चलाये रखने के लिए भ्रष्टाचार करता है। यही यथास्थिति है जिसे हम चाहें न चाहें हमें स्वीकार करना होगा। आज के समय में राजनीतिक दल बनाना और उसे चला लेना एवरेस्ट चढने से ज्यादा कठिन काम है। वह समय गया जब जनता के चंदे से नेता राजनीति करते थे और निजी जीवन में भी सत्यनिष्ठ रहते थे। अब राजनीति भी बदल गयी है और राजनेता भी। ईमानदार से ईमानदार नेता भी सीधे न सही तो परोक्ष रूप से करप्शन करता ही है वरना उसकी राजनीति का खर्चा ही नहीं निकलेगा।

इसका आशय यह नहीं कि सत्ता में बैठकर नेताओं द्वारा किये जानेवाले भ्रष्टाचार को सही मान लिया जाए। आशय सिर्फ इतना है कि समाजवादी दौर के राजनीतिक सिद्धांत पूंजीवादी दौर में लागू नहीं हो सकते। पूंजीवाद में भ्रष्टाचार वह शिष्टाचार है जिसको निभाये बिना व्यापारिक अवसर नहीं भुनाये जा सकते। इसलिए अब या तो भविष्य में राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आंदोलन होगा नहीं, अगर हुआ तो उसे जनता का समर्थन ही नहीं मिलेगा। अगर ये दोनों बातें संभव हो गयीं और उस आंदोलन से भी कोई राजनीतिक दल पैदा हो गया तो वह भी उसी दलदल का हिस्सा होगा जिसके खिलाफ आवाज बुलंद करके उसने अपना आकार पाया है। जनता को भी ऐसे राजनीतिक आंदोलनों की क्षणभंगुरता को समझ लेना चाहिए। हमारा जोर राजनीति को ठीक करने की बजाय जिस दिन समाज को ठीक करने पर हो जाएगा, राजनीति अपने आप सुधर जाएगी। इसके लिए फिलहाल कोई राजनीतिक दल प्रयास करेगा, इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। फिलहाल तो वो समाज को फुटबॉल समझकर उससे खेलने में लगे हैं।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

पाशुपतब्रह्मोपनिषद् (भाग-6)

गतांक से आगे...

जो मनुष्य ऐसा जानता है कि परमात्मा अन्तः के विषयों से भिन्न (अलग) है, वह तर्क एवं प्रमाण के बिना ही उसे अपनी अन्तरात्मा द्वारा जानने का निरन्तर प्रयास करे, उसे यथार्थ रूप में परमात्म तत्त्व का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। यह आत्मा ही परम प्रकाश स्वरूप है, जबकि वह माया महा अन्धकाररूप है। इसलिए प्रत्यगात्मा एवं माया की एकता किसी भी तरह से सम्भव नहीं है। उसके तर्कों, प्रमाणों एवं अनुभव से ज्ञात होता है कि चैतन्यमय स्वयं प्रकाशस्वरूप परमात्मा में माया नहीं है। विद्या एवं अविद्या के विषय व्यावहारिक हैं, परमात्मा से उनका कोई भी सम्बन्ध नहीं है।

तात्त्विक दृष्टि से यह सभी कुछ मिथ्या ही है। केवल एक तत्त्व ही वास्तविक सत्य है। व्यावहारिक दृष्टि से जो भी कुछ जान पड़ता है, वह भी वैसे ही आभासित होता है। प्रकाश ही निरन्तर विद्यमान है। इस प्रकार यह अद्वैत ही है, अद्वैत ही इस प्रकार के प्रकाश के अभेद से कहा जाता है। इस प्रकार से सर्वत्र सतत एक प्रकाश स्थित है। इसके सन्दर्भ में और अधिक कुछ कहने की अपेक्षा मौन ही उत्तम है। जिस मनुष्य को यह महान् ज्ञान स्वयमेव ज्ञात हो गया है, वह न जीव रूप है, न ब्रह्म है और न ही कुछ और है। उसका न कोई वर्ण है तथा वह आश्रम भी नहीं है। वह धर्म भी नहीं है और अधर्म भी नहीं है, निषेध एवं विधि भी वह नहीं है। जब उसको सब कुछ ब्रह्ममय ही दृष्टिगोचर होता है, तब उसे इस दुःखादि भेद का आभास बिल्कुल नहीं जान पड़ता। परब्रह्म परमात्मा का इस प्रकार से ज्ञान रखने वाला इस जौवादि स्वरूप वाले विश्व को देखते हुए भी नहीं देखता। वह एकमात्र चिद्रूप ब्रह्म का ही निरन्तर दर्शन करता है। धर्म एवं धर्मों के विषय-भेद के रहते हुए भिन्न ही प्रतीत होते हैं। एक मात्र वह परमात्म चेतना ही है, जो हमेशा से अपने वर्तमान स्वरूप में है और दूसरे अन्य सभी भेद आदि एवं समस्त भेद - अभेद उस (परमात्मा) में ही संव्याप्त हैं। वस्तु अथवा अवस्तु जो कुछ भी विद्यमान हैं, वह सभी कुछ साक्षात् परब्रह्ममय ही है। ऐसी दशा में ब्रह्मज्ञान रखने वाला किसी को स्वीकार अथवा परित्याग कैसे कर सकता है?

क्रमशः ...

राजिम भक्तिन माता जयंती

अनिरुद्ध जोशी

भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का राजिम क्षेत्र रायपुर जिले में महानदी के तट पर स्थित है। यहां राजिम या राजीवलोचन भगवान रामचंद्र का प्राचीन मंदिर है। राजिम का प्राचीन नाम पद्मक्षेत्र था। पद्मपुराण के पातालखण्ड अनुसार भगवान राम का इस स्थान से संबंध बताया गया है।

राजिम में महानदी और पैरी नामक नदियों का संगम है। संगम स्थल पर कुलेश्वर महादेव का प्राचीन मंदर है। इस मंदिर का संबंध राजिम की भक्तिन माता से है। कहते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के राजिम क्षेत्र राजिम माता के त्याग की कथा प्रचलित है और भगवान कुलेश्वर महादेव का आशीर्वाद इस क्षेत्र को प्राप्त है।

इसी कारण राजिम भक्तिन माता जयंती 7 जनवरी को राजिम भक्तिन माता की याद में मनाई जाती है। छत्तीसगढ़ के लाखों श्रद्धालु यहां एकत्र होकर माता की पूजा करते हैं। राजिवलोचन मंदिर में लगे शिलालेख के अनुसार कलचुरी राजा जगपाल देव के शिलालेख में माता का उल्लेख मिलता है। 3 जनवरी 1145 को शिलालेख लगाया गया था। कहते हैं कि यहां साहू समाज के लोग एकत्र होते हैं।

एक स्थानीय दंतकथा के अनुसार इस स्थान का नाम राजिव या राजिम नामक एक तैलिक स्त्री के नाम से हुआ था। कुलेश्वर मंदिर के भीतर सतीचैरा है, जिसका संबंध इसी स्त्री से हो सकता है। यहां भगवान रामचंद्र और कुलेश्वर महादेव के मंदिर के अलावा जगन्नाथ मन्दिर, भक्तमाता राजिम मन्दिर और सोमेश्वर महादेव मन्दिर भी है। इस स्थान का नाम राजिम तेलिन के नाम पर इसलिए पड़ा क्योंकि यहां के तैलिय वंश लोग तिलहन की खेती करते थे। इन्हीं तैलिन लोगों में एक धर्मदास भी था जिसकी पत्नी का नाम शांतिदेवी था। दोनों विष्णु के भक्त थे और उनकी बेटी का नाम राजिम था। राजिम का विवाह अमरदास नामक व्यक्ति से हुआ। राजिम भी विष्णु की भक्त थी जो मूर्ति विहीन राजीवलोचन मंदिर में जाकर पूजा करती थी। राजिम की भक्ति, त्याग और तपस्या के चलते ही वह संपूर्ण क्षेत्र में माता की तरह प्रसिद्ध हो गई। भगवान के प्रति अपार सेवाभाव रखने व पुण्य-प्रताप के कारण ही आज पूरे देश में राजिम भक्तिन माता की अलग पहचान है और संपूर्ण क्षेत्र को ही राजिम कहा जाता है।

राजिम का मेला- राजिम का माघ पूर्णिमा का मेला संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ के लाखों श्रद्धालु इस मेले में जुटते हैं। माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक पंद्रह दिनों का मेला लगता है। इसे राजिम कुंभ मेला भी कहते हैं। महानदी, पैरी और सोढुर नदी के तट पर लगने वाले इस मेले में मुख्य आकर्षण का केंद्र संगम पर स्थित कुलेश्वर महादेव का मंदिर है। हालांकि अब इस मेले को राजिम माघी पुन्नी मेला कहा जाता है।

हिंदुस्तान अब दो कदम आगे बढ़कर नेतृत्व करेगा

हर्ष वी. पंत

नए साल में हम एक ऐसी विश्व व्यवस्था देख रहे हैं जिसे राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक तौर पर पुनर्गठित किया गया है। पिछले कुछ वर्षों से जो रुझान सतह के नीचे थे, वे अपनी पूरी जटिलता के साथ खुलकर सामने आ गए हैं। इनसे उपजी चुनौतियों से निपटना मौजूदा ढांचे और संस्थानों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। दरअसल अंतरराष्ट्रीय संबंधों के केंद्र में एक बौद्धिक शून्य है जिसे एक शब्द के बार-बार इस्तेमाल से भरा जा रहा है। वह है- 'डिसरप्शन'। जिस चीज को भी दुनिया समझ नहीं पाती या स्वीकार नहीं कर पाती, उसे डिसरप्शन करार दिया जाता है।

सच यह है कि दुनिया बदलते शक्ति संतुलन, असाधारण तकनीकी प्रगति और संस्थानों की गिरावट के कारण आ रहे मूलभूत बदलावों से जूझ रही है। यह प्रक्रिया कोविड-19 महामारी, यूरेशिया तथा मध्य पूर्व में युद्धों के कारण और तेज हो गई है। इससे महंगाई का दबाव, भोजन और ऊर्जा का संकट तथा व्यापक आर्थिक मंदी के हालात दिख रहे हैं। तमाम देश अपने नागरिकों की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए बेतहाशा खर्च कर रहे हैं और हम सतत विकास लक्ष्यों (स्छत्र) से दूर खड़े हैं।

वैश्विक प्रतिस्पर्धा के केंद्रीय क्षेत्र हिंद-प्रशांत में भारत के सामने भी कई चुनौतियां आ खड़ी हुई हैं। इनमें बड़ी शक्तियों की आपसी प्रतिद्वंद्विता, संघर्ष, आर्थिक संकट, डी-ग्लोबलाइजेशन और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी घटनाएं शामिल हैं। हालांकि, इनमें से हर चुनौती भारत के लिए अवसर भी है। इन चुनौतियों से सही ढंग से निपटते हुए और अवसरों का उचित इस्तेमाल करके भारत विश्व व्यवस्था में अपनी हैसियत बढ़ाकर कई तरह के अहम सामरिक लाभ हासिल कर सकता है।

पिछले साल की बात करें तो भारत ने आत्मविश्वास के साथ वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाई। जी-20 की अध्यक्षता ने नई दिल्ली को कोविड-19 महामारी के साये से उबरती दुनिया में वैश्विक सहयोग के अजेंडे को आकार देने का मौका दिया। जी-20 मंच इस मायने में खास है कि यह विकसित और विकासशील देशों को एक साथ लाकर उन्हें ग्लोबल गवर्नेंस की राह में आ रही चुनौतियों पर चर्चा करने और उनके हल तलाशने का मौका देता है। नई दिल्ली ने ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया। वह भी ऐसे समय में जब कई बड़ी ताकतें अपनी घरेलू समस्याओं से इस कदर घिरी हैं कि उनके पास कमजोर देशों की मदद करने के लिए न तो समय है और न संसाधन। भारी अशांति और उथल पुथल के इस दौर में महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय जमावड़े की मेजबानी करते हुए तमाम ग्लोबल स्टेकहोल्डर्स के बीच आम सहमति बनाकर नई दिल्ली ने बड़ा सोचने और बड़े नतीजे देने की अपनी तैयारी का संकेत दिया, जिसकी दुनिया लंबे समय से भारत से उम्मीद कर रही थी।

यह न केवल प्रमुख वैश्विक गठबंधनों और बहुपक्षीय गठबंधनों में भाग लेकर, बल्कि नए गठबंधन बनाते हुए बड़ी वैश्विक भूमिका निभाने, और इस तरह जलवायु परिवर्तन, टिकाऊ विकास, वैश्विक स्वास्थ्य और शांति सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने की भारत की इच्छा के अनुरूप है। एक जिम्मेदार ग्लोबल स्टेकहोल्डर के तौर पर प्राकृतिक आपदाओं या संघर्षों के दौरान सबसे पहले प्रतिक्रिया देना भारत के वैश्विक प्रोफाइल को बढ़ाने में मददगार साबित हुआ है। हर बात पर ना कहने वाले से देश से ग्लोबल गवर्नेंस में जिम्मेदारी निभाने को तैयार देश बनने की यात्रा भारतीय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण ट्रेंड रहा है।

2023 में वर्ष दिखाई देने वाली दूसरी प्रवृत्ति थी अपनी महत्वपूर्ण साझेदारियों को लगातार संतुलित रखने की भारत की क्षमता। चुनौतियों के बावजूद प्रमुख ग्लोबल ताकतों के साथ नई दिल्ली के संबंध आगे बढ़ते रहे। यूक्रेन युद्ध ने पश्चिम के साथ भारत के संबंधों में कोई दरार पैदा नहीं की। हालांकि जब युद्ध शुरू हुआ था तब इसकी आशंका जताई जा रही थी। इसके उलट, ये रिश्ते और मजबूत होते रहे। सिख अलगाववादी नेता और अमेरिकी नागरिक गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश से जुड़े आरोपों के बावजूद भारत-अमेरिका संबंधों में गति बनी रही। क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग ङ्क क्वाड ङ्क का दोबारा उभर आना साफ इशारा है कि भारत और अमेरिका उभरती वास्तविकताओं के आधार पर एक नई साझेदारी शुरू करने के इच्छुक हैं। इसके साथ ही भारत रूस के साथ अपने करीबी रक्षा और सामरिक संबंध बनाए रखने में भी कामयाब रहा।

बीते वर्ष भारत की बाहरी भागीदारी का एक और पहलू इस बात का बढ़ता अहसास रहा कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू क्षमता निर्माण का कोई विकल्प नहीं है। केवल एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत ही चीन की बढ़ती आक्रामकता का मुकाबला कर सकता है। यदि कोविड-19 ने भारत को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता को लेकर सचेत किया, तो रूस-यूक्रेन युद्ध ने उसे रक्षा आपूर्ति के लिए दूसरों पर अति निर्भरता के खतरों से आगाह किया।

2023 में भारत का रक्षा निर्यात 15,920 करोड़ रुपये तक पहुंच गया जो 2016-17 के रक्षा निर्यात (1,521 करोड़ रुपये) के 10 गुने से भी ज्यादा है। देश के बढ़ते सैन्य-औद्योगिक क्षेत्र के लिए तो यह एक उपलब्धि है ही, सरकार की आत्मनिर्भरता मुहिम के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। यही नहीं आर्थिक मोर्चे पर इससे समान सोच वाले देशों के साथ ठोस व्यापारिक साझेदारी की संभावना और मजबूत हुई है।

मौजूदा विश्व व्यवस्था और भारत दोनों के लिए यह एक अहम मोड़ है। भारत एक बड़ी उपलब्धि की दहलीज पर खड़ा है। न केवल अगली पांत की एक ऐसी आर्थिक शक्ति के रूप में जो एक बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र भी है, बल्कि एक ऐसे जियो पॉलिटिकल प्लेयर के तौर पर भी, जो केवल संतुलन ही नहीं बनाता, नेतृत्व भी करता है। अगले कुछ वर्षों में नई दिल्ली जो फैसले करेगी, उनसे ही इस उत्कर्ष की रूपरेखा तय होगी।

आज का इतिहास

1953 अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने हाइड्रोजन बम के निर्माण की घोषणा की।
1972 स्पेन के इबीसा क्षेत्र में विमान दुर्घटना में छह चालक दल समेत 108 यात्रियों की मौत हुई।
1979 वियतनाम पीपुल्स आर्मी ने पोल पॉट और खमेर रूज को जमा करते हुए कम्बोडियाई राजधानी शहर फ्नोम पेन्ह पर कब्जा कर लिया, जिसने कम्बोडियन-वियतनामी युद्ध में बड़े पैमाने पर लड़ाई के अंत को चिह्नित किया।
1980 आपातकाल के तीन साल बाद भारी बहुमत के साथ इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हुई।
1985 सेलनेट ने 2 यूके सेल्यूलर नेटवर्क का शुभारंभ किया।
1986 अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने लीबिया के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की।
1989 जापान के वर्तमान सम्राट अकिहितो ने अपने पिता हिरोहितो की मृत्यु के बाद गद्दी संभाली, जिन्हें मरणोपरांत सम्राट शोएमा के नाम से जाना जाने लगा।
1990 पिछले 800 सालों में पहली बार पीसा की झुकती हुई मीनार को दर्शकों के लिए बंद कर दिया गया।
1993 घाना के चौथे गणराज्य का उद्घाटन इसके अध्यक्ष के रूप में जेरी रॉव्लिंग्स के साथ हुआ था।
1994 दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को सिडनी टेस्ट मैच में 5 रन से हराया।
1999 न्यूट गिंगरिच को घर के स्पीकर के रूप में फिर से चुना गया।
2007 वारसॉ स्टानिस्लाव विल्गस के नए नियुक्त आर्कबिशप ने आरोपों के बीच इस्तीफा दे दिया कि उन्होंने पोलिश कम्युनिस्ट सरकार की गुप्त पुलिस के साथ सहयोग किया।
2009 रूस के प्रधान मंत्री व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के माध्यम से यूरोप में गैस आपूर्तिकर्ताओं को बंद करने के रूस के फैसले का समर्थन किया।
2010 मुस्लिम बंदूकधारियों ने कॉप्टिक ईसाइयों की भीड़ पर आधी रात को क्रिसमस मास मनाने के बाद चर्च छोड़ कर आग लगा दी, जिनमें से आठ लोगों के साथ-साथ एक मुस्लिम उपद्रवी भी मारा गया।
2011 अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन फुटबॉल टूर्नामेंट एएफसी एशियाई कप, आधिकारिक तौर पर कतर में खुलता है।

वे चार राज्य जो भाजपा के लिए बने चुनौती

अजय सेतिया

इंडी एलायंस चार राज्यों में भाजपा से सीधा मुकाबला चुनौती देने के मंसूबे बना रहा है। कहा यह जा रहा है कि इन चारों राज्यों में भाजपा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इन चारों राज्यों की 210 लोकसभा सीटें हैं। जिनमें से भाजपा खुद पिछली बार 121 सीटें जीती थी, और सहयोगी दल 52 सीटें जीते थे। कुल मिला कर 210 में से 173 सीटें एनडीए, जबकि विपक्षी दल सिर्फ 36 सीटें जीते थे। एनडीए को पूरे देश में मिली 353 सीटों में से करीब करीब आधी सीटें इन चार राज्यों से मिली थीं।

कांग्रेस इन चारों राज्यों में ही गठबंधन करना चाहती है। ये राज्य हैं, बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। इन चार राज्यों में कांग्रेस पिछली बार पांच सीटें जीती थी, बंगाल में दो, बाकी तीनों राज्यों में एक एक। इंडी गठबंधन के बाकी दल इन चारों राज्यों में 31 सीटें जीते थे। जिनमें से 22 तृणमूल कांग्रेस, 4 एनसीपी और पांच समाजवादी पार्टी। लेकिन गठबंधन के सहयोगियों से इन चारों राज्यों में कांग्रेस 50 सीटें मांग रही है। महाराष्ट्र में 48 में से 26, उतर प्रदेश में 80 में से 10, बिहार में 40 में से 9 और बंगाल में 42 में से 5 सीटें। इनके अलावा कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में पांच और पंजाब में आठ सीटों पर दावा कर रही है। तमिलनाडु में दस सीटों पर और जम्मू कश्मीर में 3 सीटों पर दावा है। इन आठों राज्यों में कांग्रेस कुल मिला कर इंडी एलायंस के सहयोगी दलों से 85 सीटें मांग रही है।

कांग्रेस ने बाकी राज्यों में 291 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया, यानी कुल मिलाकर उसने 2024 में सिर्फ 376 सीटों की शिनाख्त की है। लेकिन महाराष्ट्र में उसे गठबंधन में 16 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली, बिहार में 5 से ज्यादा नहीं मिलने वाली, बंगाल में अगर गठबंधन हुआ, तो ममता 3 से ज्यादा सीटें नहीं देंगी।

उत्तर प्रदेश में दस सीटें जरुर मिल सकती हैं, लेकिन अगर मायावती भी गठबंधन में शामिल हुई, तो शायद यूपी में भी दस सीटें न मिलें। दिल्ली और पंजाब में अगर केजरीवाल से कांग्रेस का गठबंधन हुआ, तो वह माँगी गई 13 सीटों के बदले 8 से ज्यादा नहीं देंगे। तमिलनाडु में दस और जम्मू कश्मीर में एक सीट जम्मू की और एक सीट लद्दाख की जरुर मिल सकती है।

कुल मिला कर इंडी एलायंस से इन आठ राज्यों में कांग्रेस जहां 85 सीटें मांग रही है, वहां उसे 54- 55 सीटें ही मिलेंगी। इसका मतलब होगा कि कांग्रेस सिर्फ 345 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, जबकि 2019 में 421 सीटों पर और 2014 में 464 सीटों पर चुनाव लडी थी। 1984 में लोकसभा की 413 सीटें जीतने वाली कांग्रेस की अब उतनी सीटों पर चुनाव लड़ने की हैसियत भी नहीं बची।

सवाल यह है कि जिन चार राज्यों में गठबंधन ज्यादा महत्व रखता है। महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश। इन चारों राज्यों में क्या इंडी एलायंस भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा पाएगा। इनमें से बिहार और उत्तर प्रदेश को बिलकुल अलग कर दीजिए। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने कम्युनिस्टों के बाद कांग्रेस से भी गठबंधन करने से इंकार कर दिया है।

तीन जनवरी को खुद ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अकेले लड़ेगी। हालांकि कांग्रेस को दो सीटों की पेशकश बरकरार है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने गठबंधन की संभावना खत्म कर दी है। अगर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में गठबंधन नहीं होता, और कांग्रेस कम्युनिस्ट मिल कर चुनाव लड़ते हैं, तो बंगाल में भाजपा के सामने एक उम्मीदवार की संभावना खत्म हो जाती है। ऐसे में भाजपा को 2019 में जीती 18 सीटों को बरकरार रखना कोई मुश्किल नहीं होगा। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव के बाद बंगाल में भाजपा की ताकत बढी है, भाजपा ने अपना लक्ष्य बढा कर 35 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है।

इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, जहां पिछली बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिल कर लड़ी थी, तो भाजपा को दस सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। अगर इंडी एलायंस में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ही रहती हैं, तो भाजपा को नुकसान के बजाए कुछ फायदा ही होगा। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी भी गठबंधन में जुड़ जाती है, तो भाजपा को थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके बावजूद दो कारण हैं, जिन कारणों से भाजपा की सीटें बढ़ भी सकती हैं। पहला कारण है रामजन्मभूमि मन्दिर और दूसरा कारण है मध्यप्रदेश में एक यादव को मुख्यमंत्री बना देना। भाजपा ने उत्तर प्रदेश के यादवों में सेंध मारना शुरू कर दिया है। पिछले पन्द्रह दिन में उत्तर प्रदेश के यादवों ने दो जगह सम्मेलन करके मध्यप्रदेश में यादव मुख्यमंत्री बनाने के लिए मोदी को धन्यवाद दिया है। इस तरह के कुछ और कार्यक्रम भी किए जाएंगे।

भारतीय जनता पार्टी ने चुनौती वाले दो राज्यों बिहार और महाराष्ट्र पर फोकस कर दिया है। इन दोनों राज्यों में लोकसभा की 88 सीटें हैं, पिछली बार इन दोनों राज्यों में गठबंधन करके भाजपा ने 41 सीटें जीतीं थी। 34 सीटें सहयोगी जीते थे। इस बार इन दोनों ही राज्यों में भाजपा को बड़ी चुनौती है। 2019 के भाजपा के दो सहयोगी नेता बिहार के नीतीश कुमार और महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे अब इंडी ब्लाक में जा चुके हैं। माना यह जा रहा है कि नीतीश और उद्धव भाजपा को नुकसान पहुंचाएंगे। भाजपा के लिए संतोष की बात यह है कि नीतीश और उद्धव दोनों की अपनी पार्टियों पर पकड़ कम हुई है। बिहार में लालू यादव और कांग्रेस नीतीश कुमार को बता रहे हैं कि अब उनकी हैसियत 17 सीटों पर चुनाव लड़ने की नहीं रही। भाजपा ने जीतन राम मांझी और उपेन्द्र कुशवाहा को तो नीतीश कुमार से तोड़ ही लिया है। जेडीयू के कई सांसदों के आने वाले कुछ दिनों में भाजपा में शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस उद्धव ठाकरे को बता रही हैं कि उनकी हैसियत 23 सीटों पर चुनाव लड़ने की नहीं है। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस में टकराव बना हुआ है। भाजपा ने शिवसेना के ही दलित मराठा एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना कर डबल गेम किया है। उद्धव ठाकरे के कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने से बालासाहेब ठाकरे का कोर हिन्दू वोट एकनाथ शिंदे और भाजपा के साथ जुड़ा है।

चुनाव से पहले सीएम शिंदे ने क्यों फेंका सदियों पुराना पासा?

अंकित सिंह

महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को कम सीट होने के बावजूद भी भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि, एकनाथ शिंदे के लिए मुख्यमंत्री बनना उतना ही आसान था जितना अब लोकसभा चुनाव में पार्टी और गठबंधन के लिए जीत हासिल करना मुश्किल नजर आ रहा है। तमाम कोशिशें के बावजूद एकनाथ शिंदे शिवसेना के पारंपरिक वोट बैंक में सेंघ मारने में अब तक कामयाब नहीं हो सके हैं जिसकी भाजपा ने उम्मीद की थी। एकनाथ शिंदे के लिए एक और चुनौती यह भी है कि अजित पवार जैसे बड़े नेता अब भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के हिस्सा हैं। ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर उनके भी अपने दांव होंगे। यही कारण है कि अब एकनाथ शिंदे की ओर से हिंदुत्व वाले राग को आक्रामकता से अलापा जा रहा है। हाल में ही एकनाथ शिंदे ने दावा किया था कि वह सदियों पुरानी हाजी मंगल दरगाह की मुक्ति के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। इसी के बाद यह दरगाह सुर्खियों में बना हुआ है। दक्षिणपंथी समूह इस दरगाह के मंदिर होने का दावा करते हैं। मलंगगढ़ के सबसे निचले पठार पर स्थित, माथेरान पहाड़ी श्रृंखला पर समुद्र तल से 3,000 फीट ऊपर एक पहाड़ी किला, हाजी मलंग दरगाह हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए पूजनीय है। दरगाह चलाने वाले ट्रस्ट के सदस्यों में से एक चंद्रहास केतकर, जिनका परिवार पिछली 14 पीढ़ियों से इसका प्रबंधन कर रहा है के मुताबिक कोई भी यह दावा कर रहा है कि दरगाह एक मंदिर है, वह राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा कर रहा है। केतकर ने यह भी बताया कि 1954 में, केतकर परिवार के नियंत्रण से संबंधित एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दरगाह एक समग्र संरचना थी जिसे हिंदू या मुस्लिम कानून द्वारा शासित नहीं किया जा सकता है, बल्कि केवल अपने विशेष रिवाज या ट्रस्ट द्वारा निर्धारित नियमों के मुताबिक शासित किया जा सकता है। ट्रस्ट में हिंदू और मुस्लिम दोनों सदस्य हैं। जबकि यहां एक दरगाह बना हुआ है, हिंदू पूर्णिमा के दिन इसके परिसर में आरती करते रहते हैं। मंदिर को लेकर सांप्रदायिक झगड़े का पहला संकेत 1980 के दशक के मध्य में आया जब शिव सेना नेता आनंद दिघे ने यह दावा करते हुए एक आंदोलन शुरू किया कि यह मंदिर हिंदुओं का है क्योंकि यह 700 साल पुराने मछिंद्रनाथ मंदिर का स्थान है। 1996 में, उन्होंने 20,000 शिवसैनिकों को मंदिर में प्रार्थना करने के लिए ले जाने पर जोर दिया। उस वर्ष एक प्रार्थना में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी के साथ-साथ शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे भी शामिल हुए थे। तब से सेना और दक्षिणपंथी समूह इस संरचना को श्री मलंग गढ़ के नाम से संदर्भित करते हैं। इस आंदोलन ने दीघे की साख को चमकाने में मदद की। दीघे के शिष्य, शिंदे खुद को उनकी विरासत के उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं। यही कारण है कि उनकी ओर से यह मुद्दा उठाया जा रहा है। हाल की रिपोर्टों से संकेत मिला है कि विपक्षी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन राज्य में भाजपा-शिंदे सेना-अजित पवार एनसीपी समूह के खिलाफ मजबूत स्थिति में है। शिंदे विशेष रूप से कमजोर स्थिति में हैं, हालांकि उन्हें अदालतों द्वारा असली शिवसेना के रूप में स्वीकार किया गया है और अधिकांश विधायक और सांसद उनके पक्ष में हैं, लेकिन इसका जमीनी स्तर पर परीक्षण नहीं किया गया है। शिंदे के सामने सबसे बड़ी चुनौती शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे के अपने पिता और सेना संस्थापक बाल ठाकरे की विरासत पर स्वाभाविक दावे का मुकाबला करना है। बालासाहेब के अलावा, सेना की लड़ाई हिंदुत्व के सच्चे संरक्षक के रूप में पहचाने जाने की लड़ाई के बारे में है। शिंदे ने उद्धव पर भाजपा छोड़कर कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का आरोप लगाया है।

विपक्ष में उठापटक के बीच भाजपा में सीटों पर समझौता आखिरी दौर में!

अमित शर्मा

विपक्षी गठबंधन इंडिया के दलों में खटपट के बीच भाजपा ने अपने सहयोगी दलों से सीटों पर समझौता लगभग फाइनल कर लिया है। उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ-साथ पूर्वोत्तर के राज्यों में भी सीटों पर समझौता हो चुका है। यूपी और बिहार की चार-चार लोकसभा सीटों पर किस दल को लड़ाया जाएगा, यह विपक्षी दलों की स्थिति साफ होने के बाद तय किया जाएगा। एनडीए के सभी दलों की इस पर अंतिम सहमति भी बन गई है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में इस बार भी अनुप्रिया पटेल को पूर्वांचल की दो सीटें मिलेंगी। अपना दल (एस) को इस बार भी मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज की सीट मिलेगी। पिछले चुनाव में अपना दल (एस) ने अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए पूरी मशक्कत की थी, लेकिन भाजपा ने उनकी बात नहीं मानी। इस बार भी भाजपा उनकी सीटों की संख्या नहीं बढ़ाएगी और इस पर दोनों दलों में सहमति बन गई है। यूपी में भाजपा के भरोसेमंद सहयोगी बनकर उभरी निषाद पार्टी के प्रवीण निषाद को इस बार भी भाजपा के टिकट पर मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं, अखिलेश यादव से खटपट के बाद भाजपा के खेमे से मजबूती से बैटिंग कर रहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को एक टिकट मिल सकता है। उनकी पार्टी के उम्मीदवार को वाराणसी के पास की एक राजभर जाति बहुल सीट से भाजपा के टिकट पर उतारा जा सकता है। राजभर को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ज्यादा हिस्सेदारी देकर उनको संतुष्ट करने की कोशिश की जा सकती है। इसी बीच यूपी में विपक्षी दलों के बीच से दो प्रतिष्ठित नेता भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में इन सीटों पर उन्हीं उम्मीदवारों को भाजपा के टिकट पर उतारा जा सकता है। ये दोनों सीटें पूर्वांचल की हैं। भाजपा सूत्रों के अनुसार, इसी प्रकार बिहार में भी सहयोगी दलों में समझौते को लेकर सहमति बन गई है। लोजपा को एक करते हुए उसे एक बार फिर छह सीटें दी जा सकती हैं, तो जीतनराम मांझी को एक से दो सीटें मिल सकती हैं। दो सीटों पर अभी अंतिम सहमति नहीं बन पाई है कि इन सीटों पर किस दल को चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाएगा। इन सीटों पर विपक्षी खेमे के दल-उम्मीदवार की स्थिति साफ होने के बाद अंतिम निर्णय किया जाएगा। बिहार में भाजपा का गणित नीतीश कुमार के कारण अटक सकता है, क्योंकि अभी भी इस बात की संभावना जताई जा रही है कि वे पासा पलट कर भाजपा के खेमे में आ सकते हैं। यदि वे एक बार फिर एनडीए में आते हैं, तो सीटों के बंटवारे में बड़ा उलटफेर हो सकता है। सीटों के चयन पर भी पुनर्विचार करने की जरूरत पड़ सकती है।

दक्षिण की 132 सीटों का ऐसा है इतिहास

शिवेंद्र तिवारी

साल शुरू होते ही लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। विपक्षी गठबंधन में जहां सीट बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है। वहीं, भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा तक अलग-अलग राज्यों में रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी साल की शुरुआत होते ही दक्षिण के राज्य केरल और केंद्र शासित लक्ष्यद्वीप पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। रोड शो भी किया साथ ही रैली भी की। कई राजनीतिक विश्लेषक इसे भाजपा का मिशन दक्षिण कह रहे हैं। आखिर दक्षिण का सियासी गणित क्या है? देश के दक्षिणी हिस्से में भाजपा का अब तक का प्रदर्शन कैसा रहा है? कांग्रेस यहां कैसा प्रदर्शन करती रही है? लोकसभा की कितनी सीटें दक्षिण से आती हैं? किस राज्य में किस पार्टी की पकड़ है? आइये समझते हैं-

543 सदस्यीय लोकसभा में देश के दक्षिण से 132 सीटें आती हैं। इनमें सीटों के लिहाज से तमिलनाडु सबसे बड़ा राज्य है। यहां से कुल 39 सांसद चुनकर आते हैं। कर्नाटक से 28, आंध्र प्रदेश से 25 और केरल से 20 सांसद लोकसभा पहुंचते हैं। इसी तरह तेलंगाना से 17, पुडुचेरी, लक्ष्यद्वीप और अंडमान निकोबार से एक-एक सांसद चुनकर आते हैं। इस तरह दक्षिण भारत के पांच राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 132 लोकसभा सीटें हैं।

पिछले लोकसभा चुनाव में दक्षिण की 132 सीटों में से 29-29 सीटें भाजपा और कांग्रेस दोनों के खाते में गईं थीं। वहीं, अन्य दलों के हिस्से में 74 सीटें आईं थीं। इनमें तमिलनाडु की 24 सीटें डीएमके और आंध्र प्रदेश की 22 सीटें वाईएसआर कांग्रेस ने जीतीं थीं। भाजपा को सिर्फ दो राज्यों में जीत मिली थी। पार्टी कर्नाटक की 28 में से 25 सीटें जीतने में सफल रही थी। वहीं, तेलंगाना की 17 में से

चार सीटों पर पार्टी को सफलता मिली थी। अन्य किसी राज्य में भाजपा का खाता भी नहीं खुला था।

वहीं, कांग्रेस को सबसे ज्यादा सफलता केरल में मिली थी। यहां की 20 में से 15 सीटों पर पार्टी जीतने में सफल रही। 39 सीटों वाले तमिलनाडु में पार्टी को आठ सीटों पर जीत मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने डीएमके के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। राज्य की नौ सीटों पर चुनाव लड़ी कांग्रेस को आठ में जीत मिली। इसी तरह 24 सीटों पर चुनाव लड़ी डीएमके सभी सीटें जीतने में सफल रही थी। विपक्षी एआईएडीएमको महज एक सीट से संतोष करना पड़ा था। तेलंगाना में कांग्रेस को तीन सीटों पर जीत मिली थी। तेलंगाना में हाल ही में कांग्रेस सत्ता में आई है। इससे पहले पार्टी को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी जीत मिली थी। यहां, 2019 में उसे महज एक सीट से संतोष करना पड़ा था। इसके अलावा पार्टी पुडुचेरी और अंडमान-निकोबार में भी एक-एक सीट पर जीतने में सफल रही थी।

2019 के लोकसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतने वाली भाजपा के लिए दक्षिण बड़ी चुनौती साबित हुआ था। इसके बाद भी दक्षिण में 2019 का प्रदर्शन भाजपा का सर्वश्रेठ था। 2019 से से पहले भाजपा दक्षिण में कभी भी 25 से ज्यादा सीटें नहीं जीत सकी थी।

इससे पहले दक्षिण में भाजपा को अधिकतम 22 सीटें जीतने में सफल रही थी। यह प्रदर्शन उसने 2014 में किया था। बीते कई चुनाव से चुनाव दर चुनाव पार्टी की सीटें इस इलाके में बढ़ रही हैं। 2009 में पार्टी को दक्षिण में 20 सीटें, 2004 में 18 सीटें, 1999 में 19 सीटें, 1998 में 16 सीटें मिलीं थीं। इससे पहले के चुनावों में पार्टी कभी भी दक्षिण में 10 सीटें भी नहीं जीत सकी थी। पार्टी बनने के बाद 1984 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में भाजपा दक्षिण में खाता खोलने में सफल रही थी। उसे आंध्र प्रदेश में एक सीट मिली थी। इसके बाद 1989 में उसे कोई सीट नहीं मिली। 1991 में पार्टी को कर्नाटक में चार तो आंध्र प्रदेश में एक सीट पर जीत मिली थी। वहीं, 1996 में पार्टी दक्षिण की छह सीटें जीतने में सफल रही थी। ये सभी सीटें कर्नाटक की थीं। बीते दस चुनावों की बात करें तो कांग्रेस का दक्षिण में सबसे बेहतर प्रदर्शन 1989 में था। जब पार्टी ने 110 सीटें इस इलाके में जीती थीं। जबकि सबसे कम 19 सीटें 2014 में मिली थीं। 2019 में पार्टी के प्रदर्शन में सुधार हुआ और उसे 29 सीटों पर कामयाबी मिली। हालांकि, 2014 से पहले के नतीजों के मुकाबले यह काफी कम था। 2004 में कांग्रेस को दक्षिण में 48 तो 2009 में 62 सीटों पर जीत मिली थी। इसी तरह कांग्रेस की 1999 में 35, 1998 में 45, 1996 में 37, 1991 में 92 और 1984 में 71 सीटें दक्षिण से आईं थीं।

साल की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री मोदी केरल के दो दिन के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने लक्ष्यद्वीप में भी कई कार्यक्रम किए। पीएम मोदी केरल में महिलाओं से भी संवाद किया। भाजपा ने आयोजन से पहले ही दावा किया कि इस संवाद में दो लाख महिलाएं जुटेंगी। वैसे भी भाजपा अपनी सफलता में महिलाओं की हिस्सेदारी को बड़ा कारण बताती रही है। इस पूरे दौरे को भाजपा के 2024 के चुनावी प्लान से जोड़कर देखा जा रहा है। ये पहला मौका नहीं है जब यह दिखा हो कि भाजपा ने दक्षिण की ओर फोकस बढ़ाया है। बीते 12 महीने में ही कई ऐसे संकेत मिल चुके हैं।

आखिर इंडी गठबंधन में मायावती को शामिल क्यों नहीं होने देना चाहते अखिलेश?

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तब तक कोई गठबंधन कामयाब नहीं माना जा सकता है जब तक कि उसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ नजर नहीं आयें। 2019 के यानी पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बाद नंबर दो पर रही बसपा को सबसे अधिक वोट मिले थे और सपा को बसपा के मुकाबले करीब डेढ़ फीसदी कम वोट पड़े थे। बाकी दल चाहे उसमें राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कांग्रेस हो या फिर पश्चिमी यूपी तक सीमित राष्ट्रीय लोकदल, इन दोनों दलों की इतनी ताकत नहीं है कि वह सपा-बसपा के बिना कोई बड़ा उलटफेर कर सकें। वैसे इन दलों के अलावा अपना दल (सोनेलाल), निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल (कमेरावादी), जनता दल यूनाइटेड, आजाद समाज पार्टी, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक एवं एआईएमआईएम जैसी पार्टियां भी हैं जिनका पिछले उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में वोट एक प्रतिशत के नीचे ही रहा था। अपना दल सोनेलाल गुट जो बीजेपी के साथ है, उसको जरूर डेढ़ प्रतिशत से कुछ ज्यादा वोट मिले थे। इन दलों का यही हाल कमोवेश 2019 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। यह आंकड़े उन लोगों के लिए एक संदेश हैं जो यूपी में इन दलों को साथ लेकर कोई बड़ा उलटफेर का सपना संजोये हुए हैं।

2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के बल पर अपनी ताकत बढ़ाने में लगे गैर बीजेपी दलों के लिए 2017 के उत्तर प्रदेश विधान सभा और 2019 के लोकसभा चुनाव एक बानगी है। 2017 का विधान सभा चुनाव समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन जनता ने इसे पूरी तरह से ठुकरा दिया और इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा-बसपा गठबंधन भी कुछ खास नहीं कर पाया था। आश्चर्यजनक बात यह है कि समाजवादी पार्टी नेता इस हकीकत से

अनभिज्ञ नहीं हैं, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव क्यों बसपा को साथ नहीं लेना चाहते हैं, यह रहस्य बना हुआ है। जबकि कांग्रेस खुलकर कह चुकी है कि वह इंडी गठबंधन में बसपा को भी देखना चाहती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बसपा का ठीकठाक वोट बैंक है। दलितों में उनकी अच्छी खासी पैठ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सपा-बसपा मिलकर चुनाव लड़े थे, तब बसपा को 19.88 फीसदी वोट मिले थे, जो सपा से कुछ ज्यादा ही थे। सपा को 18.11 फीसदी मत हासिल हुए थे।

बहरहाल, गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी शामिल होगी या नहीं, इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। हालांकि गैर बीजेपी गठबंधन वाले नेता और अन्य वर्ग के लोग बसपा को इंडी गठबंधन में शामिल करने की मांग लगातार उठा रहे हैं। परंतु अखिलेश अपनी बात पर अड़े हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों दिल्ली में गठबंधन की बैठक में भी जब इस पर बात हुई तो सपा ने आपत्ति जताई थी। सपा ने दो टूक कह दिया था कि बसपा आएगी तो वह बाहर निकल जाएगी। अब यूपी कांग्रेस से मांग उठी है कि गठबंधन में बसपा को भी शामिल किया जाए। दरअसल, कांग्रेस पार्टी भाजपा को 2024 में शिकस्त देने के लिए अपनी तरकश के हर तीन आजमाना लेना चाहती है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दलित वोटरों में मायावती की पैठ को देखते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व से कहा है कि मायावती साथ आईं तो दलित वोट मिलना आसान हो जाएगा। यूपी में 20 प्रतिशत आबादी दलितों की है।

मायावती की चर्चा चलने लगी तो बसपा के सांसद मलूक नागर आगे आये और उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाना शुरू कर दिया और मांग की कि पार्टी प्रमुख मायावती को पीएम पद का प्रत्याशी घोषित किया जाए। उनसे पूछा गया था कि इंडी गठबंधन में शामिल होने के लिए पार्टी की क्या कोई शर्त होगी? उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हमारे पार्टी के विधायकों को ले जाने के लिए मायावती जी से माफी मांगनी चाहिए और उन्हें इंडी गठबंधन का पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। नागर ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस दलित चेहरा चाहती है तो मायावती से बेहतर कोई पीएम कैंडिडेट नहीं मिल सकता है। नागर ने कहा कि उनकी पार्टी का यूपी में 13.5 प्रतिशत दलित वोट शेयर है। उन्होंने यह भी दावा कर दिया कि मायावती को पीएम फेस बनाया जाता है तो हम 60 से ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। खैर, इससे इतर इंडी गठबंधन के भीतर अभी यूपी की सीटों के बंटवारे पर मंथन चल रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख बता रहे हैं कि यूपी में कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी और रालोद को कितनी सीटें दी जायेंगी। कांग्रेस को करीब 15 और रालोद को पांच से छह सीटें दिये जाने की संभावना है। सपा करीब 58 सीटों पर लड़ना चाहती है, लेकिन बसपा के गठबंधन में शामिल होने से सभी दलों की सीटों में कटौती निश्चित है। पिछले दिनों विपक्ष की बैठक के बाद मायावती ने सामने आकर कहा था कि भविष्य में देश में जनहित में कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए, कहा नहीं जा सकता है। दरअसल, मायावती को भी पता है कि भाजपा के जनाधार को देखते हुए बसपा के लिए बेहतर प्रदर्शन कर पाना चुनौती होगी। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा को 10 सीटें मिली थीं। अपने दम पर शायद इस बार उतनी सीटें न मिलें, ऐसे में बसपा भी चाहेगी कि वह गठबंधन में आकर अच्छा प्रदर्शन कर सके।

2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने सपा और राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। इसे करीब 40 प्रतिशत वोट मिले थे। बसपा को करीब 20 प्रतिशत, सपा को 19 और रालोद को 1.69 प्रतिशत वोट मिले थे। बसपा के बारे में देखा गया है कि वह बहुत पहले अपने उम्मीदवार घोषित कर देती है लेकिन इस बार उसने प्रभारी भी नहीं बनाए हैं। बसपा के लोग मान रहे हैं कि हो सकता है कि गठबंधन को लेकर जल्दी स्थिति साफ हो।

उधर, बसपा को इंडी गठबंधन से दूर रखने की समाजवादी कोशिश की बात की जाये तो सपा कम से कम सीटों का बंटवारा करना चाहती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जानते हैं कि जब गठबंधन में सीटों का बंटवारा होगा तो 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे इसका आधार बनेंगे और उन चुनावों में बसपा को सपा से अधिक वोट और सीटें मिली थी, जिसके चलते उसकी दावेदारी भी ज्यादा मजबूत होगी। बसपा किसी भी सूरत में सपा से कम सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं होगी। इसीलिए अखिलेश बसपा को गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने देना चाहते हैं, इसके लिए अखिलेश यादव यहां तक कहने लगे हैं कि यदि बसपा को गठबंधन में शामिल किया गया तो वह गठबंधन से अलग भी हो सकते हैं।

दरअसल, अखिलेश चाहते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव के आधार पर लोकसभा सीटों का बंटवारा हो, जिसके नतीजे कांग्रेस और बसपा के लिए बेहद निराशाजनक रहे थे। 2007 में प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार का मुख्यमंत्री पद संभाल चुकीं मायावती की पार्टी को 15 साल बाद 2022 में मात्र एक विधान सभा सीट मिली थी। समाजवादी पार्टी कुछ भी दलील दे, लेकिन कांग्रेस की दिली तमन्ना यही है कि बसपा को भी गठबंधन का हिस्सा बनाया जाये। जो सही भी है, यदि बसपा भी इंडी एलायंस का गठबंधन का हिस्सा होती है तो यूपी में कई लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का समीकरण गड़बड़ा सकता है।

उधर, सपा की बात की जाये तो उसके लिये भी राह आसान नही नजर आ रही है। उसके अपने ही उसका साथ छोड़ते जा रहे हैं। हालत यह है कि इंडिया गठबंधन में शामिल होकर पीडीए का झंडा थामने में लगे अखिलेश यादव से अब परंपरागत यादव वोट बैंक भी खिसक रहा है। सालों से मुलायम सिंह यादव की सरपरस्ती में चल रही अखिल भारतीय यादव महासभा में दो फाड़ हो गया है। यूपी में यादव तबके ने यादव मंच बना कर सपा की सियासत की छाया से खुद को अलग कर लिया है। यादव महासभा का सपा से मोह भंग होना अखिलेश यादव के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। ओबीसी कुनबे को इकट्ठा करने में जुटे अखिलेश यादव को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा झटका लगा है। दरअसल, अखिल भारतीय यादव महासभा का हमेशा सपा को समर्थन मिलता रहा है लेकिन बीते कुछ सालों के दौरान सपा और महासभा के बीच खटपट बढ़ी है।

आलिया की जगह वरुण की दुल्हनिया 3 बनेंगी जान्हवी

करण जौहर के 'स्टूडेंट' वरुण धवन एक बार फिर दूल्हा बनने की तैयारी कर रहे हैं । बॉलीवुड हंगामा ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक करते हुए हाल ही में बताया था कि, करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस अपनी हिट दुल्हनीय फ्रेंचाइज़ी को आगे बढ़ाते हुए इसकी तीसरी किस्त, यानी दुल्हनिया 3 बनाने वाले हैं । बॉलीवुड हंगामा ने ये भी बताया था कि, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया और बद्रीनाथ की दुल्हनिया से दर्शकों का दिल जीतने वाले वरुण धवन दुल्हनिया 3 में भी दूल्हा बनने वाले हैं । जहां मेकर्स ने दुल्हा के रूप में वरुण धवन को फिर से फ़ाइनल कर लिया था वहीं आलिया भट्ट की जगह फ़िल्म में एक नई दुल्हनिया को लॉंच करने की तैयारी की जा रही थी । इसी बीच खबर आई कि दुल्हनिया 3 में मेकर्स आलिया भट्ट की जगह जाह्नवी कपूर को कास्ट करने का फ़ैसला कर चुके हैं । और अब इसी खबर पर प्रोड्यूसर करण जौहर ने चुप्पी तोड़ी है ।

पीपिंगमून की खबर के मुताबिक, जान्हवी कपूर करण जौहर की दुल्हनिया फ्रेंचाइजी की नई दुल्हनिया होंगी । रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि, आलिया भट्ट ने डेट्स इश्यू के चलते इस फ़िल्म से इंकार कर दिया है । और अब धर्मा प्रोडक्शंस के करण जौहर ने इन दावों का खंडन करते हुए क्लीयर किया कि ये केवल अनुमान हैं और झूठ हैं । अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने लिखा, हर सुबह मैं ऐसी खबरें देखता हूं, जिनकी धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है...मीडिया के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि कृपया किसी फ्रेंचाइजी की निरंतरता या किसी की शुरुआत के बारे में अनुमान न लगाएं ! समय और योजनाएं बनने और फाइनल होने पर हम विवरण देंगे ! हम अपनी भविष्य की फिल्मों को लेकर दिखाए गए उत्साह से अभिभूत हैं, लेकिन अटकलों के बजाय सटीकता को पसंद करेंगे... आदरपूर्वक, करण जौहर । वरुण, शशांक और करण जौहर ने दुल्हनिया 3 के लिए कई विचारों पर चर्चा की है और आखिरकार एक पर फैसला कर लिया है । फिल्म 2024 के अंत में फ्लोर पर जाने के लिए पूरी तरह तैयार है और निर्माताओं ने वरुण की दुल्हनिया का किरदार निभाने के लिए एक नई अभिनेत्री की तलाश शुरू कर दी है । करण और वरुण नई दुल्हनिया के साथ बॉलीवुड में एक नया चेहरा लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं ।

ऋतिक व पादुकोण की फाइटर का पायलट थीम सॉन्ग 'हीर आसमानी' कल होगा आउट

जबकि सिद्धार्थ आनंद की अपकमिंग फाइटर के टीज़र ने इसकी एक्शन से भरपूर दुनिया की हल्की सी झलक दी, फिल्म के गानें वास्तव में लोगों के उत्साह को नेक्स्ट लेवल पर गए है। जी हां, जहां पहले रिलीज़ हुए गाने, 'शेर खुल गए' और 'इश्क जैसा कुछ' मजेदार पार्टी एंथम के रूप में आए है, वहीं अब मेकर्स पायलट थीम गीत 'हीर आसमानी' के साथ भारतीय एयर फोर्स की भावना का जश्न मनाने के लिए तैयार हो रहे हैं और जिसकी झलक टीज़र से मिलती है। 'हीर आसमानी' गाने का टीजर रिलीज हो गया है और सारा माहौल अच्छी वाइब्स से भरा हुआ है । इसमें देशभक्ति का जुनून है, ये तेज बीट वाला गाना हमारे आसमान और देश की सुरक्षा में लगे फाइटर पायलटों को समर्पित है । टीज़र में ऋतिक और दीपिका के अलावा पूरी कास्ट भी दिख रही है । जब वो चलते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक से पता चलता है कि एक फुल-ऑन एनर्जेटिक गाना आने वाला है । टीज़र आ गया है, पर हम सब 8 जनवरी, सोमवार को हीर आसमानी की रिलीज़ देखने के लिए बेचैन हैं। ज़मीन वालों को समझ नहीं आनी मेरी. सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में और वायकॉम18 स्टूडियोज और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स के सहयोग से प्रस्तुत फाइटर एक सिनेमाई अनुभव है। यह फिल्म

दिल दहला देने वाले एक्शन सीन्स को देशभक्ति के उत्साह के साथ सहजता से पेश करती है, जो एक ए` स` ग ह न अनुभव का वादा करती है जो दुनिया भर के दर्शकों को पसंद आएगा।

इन फैशनेबल ट्रिक्स के साथ सर्दियों में अपने स्टाइल को बरकरार रख रहे हैं टीवी कलाकार!

सर्दियों का ठंडा मौसम आने के साथ ही फैशन में भी बदलाव आ जाता है और स्टाइल का संगम गर्माहट से कर दिया जाता है। एण्डटीवी के कलाकार स्क्रीन पर अपने आकर्षण को लेकर जाने जाते हैं। उन्होंने स्टाइल से समझौता किये बिना अपने वार्डरोब्स को नयापन देने का एक फैशनेबल सफर शुरू कर दिया है। मौसम के बदलाव को अपनाते हुए, यह कलाकार अपने सीक्रेट्स और अनोखे विंटर फैशन स्टाइल के बारे में बता रहे हैं। इस तरह से फैशन के शौकीन लोगों को प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलेगा, ताकि वे सर्दियों के लिये ट्रेंडी, लेकिन आरामदायक कपड़ों को चुन सकें। हमारे यह कलाकार हैं राहुल जेठवा (अवध बिहारी वाजपेयी, 'अटल'), गीतांजलि मिश्रा (राजेश, 'हप्पू की उलटन पलटन') और विदिशा श्रीवास्तव (अनीता भाबी, 'भाबीजी घर पर हैं')। एण्डटीवी के 'अटल' में अवध बिहारी वाजपेयी की भूमिका निभा रहे राहुल जेठवा ने कहा, ''मुझे सर्दियों का मौसम अपने स्टाइल के साथ प्रयोग करने के लिये सबसे प्रेरक लगता है। मैं लूज-फिटिंग वाला लाइट ब्लू डेनिम जैकेट या ग्रे हूड लेयर्ड और एक प्रिंटेड व्हाइट टी-शर्ट लेता हूँ। इसके साथ एंकल-लेंथ लाइट ब्लू जींस और आकर्षक काले, ऊँची हील वाले बूट पहनता हूँ। सर्दियों के लिये मेरा एक और पसंदीदा लुक है स्लिम-फिट पैंट्स और फॉर्मल शूज के साथ मैचिंग वाले टर्टलनेक टी-शर्ट्स पहनना। इससे मुझे हमेशा बेहतर एहसास होता है। मेरी माँ ने मुझे हाल ही में एक स्टाइलिश ग्रे कैशमेयर क्रूनेक स्वेटर दिया था। मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने वह मेरे लिये खरीदा नहीं था, बल्कि खास मेरे लिये अपने हाथों से बनाया था। यह कार्डिगन स्वेटर परफेक्ट तरीके से मेरे कंधों पर फिट हो जाता है और काफी वर्सेटाइल है। यह आसानी से किसी भी प्लेन टी-शर्ट, बटन-डाउन शर्ट, ब्लैजर या जीन्स के साथ मेल खाता है। एसेसरी के तौर पर मैं अक्सर इसके साथ चेकरेड प्रिंट स्कार्फ पहनता हूँ, ताकि मेरे आउटफिट की रौनक बढ़ जाए।''

'हप्पू की उलटन पलटन' की राजेश, ऊर्फ गीतांजलि मिश्रा ने बताया, ''मैंने हाल ही में रात के तापमान में बड़ी गिरावट देखी है। और मैंने अपने वार्डरोब को आने वाले महीनों के लिये तैयार कर लिया है। मैं पूरे दिन हल्की-फुल्की कॉटन कुर्तियाँ पहनती हूँ। हालांकि सूरज ढलने पर मैं वुलन जैकेट पहन लेती हूँ, जिसे मैंने हाल ही में लखनऊ के मशहूर अमीनाबाद बाजार से खरीदा था। इसके अलावा, मैंने शरीर को गर्म रखने के लिये अपने रोजाना के कपड़ों के नीचे थर्मल वियर पहनना शुरू कर दिया है। अपने लुक में नयापन लाने के लिये मैं कई तरह के आकर्षक शॉल ओढ़ती हूँ। हर शॉल को बड़े ही प्यार से हर बारीकी पर ध्यान देकर बनाया गया है। यह शॉल्स भारत के अलग-अलग राज्यों के विविध रंगों और संस्कृतियों से प्रेरित हैं। मैं अपने किरदार के लुक में कभी-कभी इनका इस्तेमाल करती हूँ और यह राजेश के लुक से बखूबी मेल खाते हैं। साथ ही मुझे सर्दी भी नहीं लगती और मेरा स्टाइल बरकरार रहता है। मैं सभी को सर्दियों के एक खुशनुमा मौसम की शुभकामना देती हूँ!'' 'भाबीजी घर पर हैं' में अनीता भाबी बनीं विदिशा श्रीवास्तव ने बताया, ''मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ, जहाँ सर्दियों में मौसम बहुत सुहावना हो जाता हो जाता है। इस मौसम में जलवायु कभी आरामदायक, तो कभी-कभी बेहद ठंडी हो जाती है। सर्दियों के दौरान मेरी माँ हमारे वार्डरोब्स को जैकेट्स, ओवरकोट्स, स्कल कैप्स, मिटन्स, मफलर्स, स्कार्व्स और थर्मल वियर से भर दिया करती थीं। कई बार तो उन्होंने बड़ी कुशलता से हमारे लिये आकर्षक मिटन्स, स्वेटर्स और मफलर्स बुने। इन चीजों को हम बड़ी खुशी और गर्व के साथ पहना करते थे। उनमें से कुछ तो अब भी मेरी अलमारी में हैं और मुझे इसका बेसब्री से इंतजार है कि मेरी बेटी आद्या उन्हें पहनेगी। ऐसे मौसम में गर्म रहने के लिये लेयरिंग वाली क्लॉथिंग जरूरी हो जाती है। मुझे मुंबई की सर्दियाँ पसंद हैं, क्योंकि यहाँ मौसम खुशनुमा रहता है, यहां ज्यादा ठंड नहीं पड़ती। यह देखकर मैं मोनोक्रोमैटिक एन्सेंबल्स चुनती हूँ। या सर्दियों के दौरान अपने रोजाना के कपड़ों के साथ साधारण-सा एक स्कार्फ पहन लेती हूँ, ताकि शरीर को गर्म रखने के साथ ही स्टाइलिश भी दिखूं!''

टी-सीरीज़ ने ख़रीदे जूनियर एनटीआर स्टारर देवरा के म्यूज़िक राइट्स ; कल रिलीज होगा टीज़र

जूनियर एनटीआर अभिनीत आगामी मोशन पिक्चर फिल्म देवरा- पार्ट 1 के बारे में एक और रोमांचक अपडेट को चिह्नित करते हुए, भूषण कुमार संगीत दिग्गज टी-सीरीज़ ने विशेष रूप से सभी भाषाओं में फिल्म के संगीत अधिकार हासिल कर लिए हैं । कोराताला शिव द्वारा निर्देशित और युवासुधा आर्ट्स और एनटीआर आर्ट्स द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित, यह फिल्म नंदमुरी कल्याण राम द्वारा प्रस्तुत की गई है । अनिरुद्ध रविचंदर, जो देश के सबसे प्रतिभाशाली नए जमाने के संगीतकारों में से एक के रूप में प्रसिद्ध हैं, फिल्म के संगीत का प्रबंधन करते हैं, जिन्होंने पहले हाल के वर्षों में कुछ सबसे बड़े संगीत हिट तैयार किए हैं।

टी-सीरीज़ ने हासिल किए जूनियर एनटीआर की देवरा के म्यूज़िक राइट्स सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा करते हुए, देवरा- पार्ट 1 के निर्माताओं ने लिखा, "#Tseries इस लहर में शामिल हो गया है! मैन ऑफ मासेस सहड्डत्र के सदेवरा

ऑडियो राइट्स @Tseries @Tseriessouth को मिले @anirudhofficial की एड्रेनालाईन से भरी डर की आवाज आपके रोंगटे खड़े कर देने और आपको बेचैन अवस्था में ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार है ।

मैन ऑफ मासेस एनटीआर जूनियर इस सामूहिक मनोरंजनकर्ता और दूरदर्शी कोराटाला शिव के निर्देशन में अनिरुद्ध रविचंदर के शानदार संगीत के साथ निर्देशन कर रहे हैं, कोई भी देवरा- भाग 1 और इसके संगीत से असाधारण पेशकश से कम की उम्मीद नहीं कर सकता है, जो सभी भाषाओं में उपलब्ध होगा । इस बीच, फिल्म की पहली झलक 8 जनवरी को रिलीज होने वाली है, जिससे प्रशंसकों का उत्साह अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है । 5 अप्रैल, 2024 को स्क्रीन पर आने की उम्मीद है, देवरा- पार्ट 1 में सह-कलाकार सैफ अली खान और जान्हवी कपूर प्रमुख भूमिकाओं में हैं । फिल्म की सिनेमैटोग्राफी प्रशंसित आर रत्नावेलु द्वारा संभाली गई है ।

ब्रेकअप की अफवाहों के बीच सामने आई मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर की शादी की खुशनुमा तस्वीर, नेटिज़न्स बोले- अब इनकी भी हो जाए

मलायका अरोड़ा और अर्जुन कपूर काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वे एक-दूसरे के प्यार में पागल हैं और इसका प्रमाण सोशल मीडिया पर उनके द्वारा साझा की गई भावपूर्ण तस्वीरों से मिलता है। कुछ साल पहले की बात है जब अर्जुन कपूर के जन्मदिन पर मलायका अरोड़ा ने इंस्टा पर उनके साथ अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया था। तब से, उन्होंने प्रशंसकों को अपने जीवन की एक झलक दिखाने के लिए एक साथ कई तस्वीरें साझा की हैं। हालाँकि, हाल ही में ऐसी अफवाहें थीं कि अर्जुन कपूर और मलायका अरोड़ा का ब्रेकअप हो गया है। जूम की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि दो महीने पहले उनका ब्रेकअप हो गया था लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते को एक और मौका देने के लिए समझौता कर लिया है। इन सबके बीच, एक शादी से मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर की एक तस्वीर वेब पर सामने आई है। करिश्मा करमचंदानी की शादी में अन्य लोगों के साथ पोज देते हुए मलायका अरोड़ा और अर्जुन कपूर की एक तस्वीर ने वेब पर अपनी जगह बना ली है। दोनों एक-दूसरे के करीब खड़े होकर मुस्कुराते हुए खुशी से कैमरे के सामने पोज दे रहे हैं। लेमन ग्रीन आउटफिट में मलाइका बेहद खूबसूरत लग रही हैं जबकि अर्जुन अपने देसी अवतार में हैं। जैसे ही तस्वीर एक पपराज़ी द्वारा साझा की गई, नेटिज़न्स टिप्पणी कर रहे हैं और कामना कर रहे हैं कि मलाइका और अर्जुन भी जल्द ही शादी कर लें। एक टिप्पणी में लिखा था, अब इनकी भी हो जय नए साल की शादी। हमें यह कहना ही होगा कि मलायका और अर्जुन एक खूबसूरत जोड़ी हैं। अक्सर सितारों से उनकी शादी की योजना के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। दरअसल, हाल ही में फराह खान ने मलायका अरोड़ा से सवाल किया था कि क्या वह 2024 में शादी करने के लिए तैयार हैं। इस पर दिवा ने मजेदार जवाब देते हुए कहा, एक बार काटे, दो बार शर्माएं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई पूछेगा तो वह ऐसा करेंगी। ऐसा तब हुआ जब उनके पूर्व पति अरबाज खान ने शूरा खान से शादी कर ली। अलग होने से पहले अरबाज और मलायका की शादी करीब दो दशक तक चली थी। फिर मलाईका को अर्जुन कपूर में प्यार मिला और वह कुछ सालों से लगातार रिलेशनशिप में हैं।

हीरानी का बुलावा आते ही 'डंकी' में अपनी भूमिका निभाने पहुँच गए थे गौड़

रोहिताश्व गौड़ एण्डटीवी के लोकप्रिय शो 'भाबीजी घर पर हैं' में अपने मशहूर किरदार मनमोहन तिवारी के चलते सबके चहेते बन चुके हैं। उन्होंने टेलीविजन और बॉलीवुड में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। उनकी बेजोड़ कॉमिक टाइमिंग ने मनोरंजन उद्योग के एक प्रतिभाशाली कलाकार के तौर पर उन्हें मजबूती से स्थापित किया है। गौड़ ने हाल ही में राजकुमार हीरानी की फिल्म डंकी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसमें वे एक धोखेबाज वीजा एजेंट के किरदार में नजर आये। एक बेबाक बातचीत में उन्होंने विस्तार से बताया है कि उन्हें यह भूमिका कैसे मिली।

शाहरुख खान की फिल्म से जुड़ने के बारे में रोहिताश्व गौड़ ने बताया, ''यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यह मेरे लिये सबसे महत्वपूर्ण मौकों में से एक बन गया, और इसके लिए मुझे बहुत कम इंतजार करना पड़ा। दिलचस्प बात यह है, कि यह सब एक ही दिन में हो गया। मैं नायगांव में अपने शो 'भाबीजी घर पर हैं' की शूटिंग कर रहा हूँ। लगातार सफर करने से बचने के लिये मैं आमतौर पर सेट के पास के एक अपार्टमेंट में ठहरता हूँ और सिर्फ छुट्टी के दिनों में अपने घर गोरेगांव जाता हूँ। हमें अगले दिन शूटिंग करनी थी, लेकिन मुझे सुबह ही खबर मिली कि सेट पर एक हफ्ते की छुट्टी है। मैंने सोचा कि इस वक्त का इस्तेमाल घर जाकर अपने परिवार के साथ बिताने के लिये करना चाहिये। रास्ते में मुझे राजकुमार हीरानी जी का कॉल आया और उन्होंने पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मैं घर जा रहा हूँ और उन्होंने ज्यादा कुछ कहे बिना मुझे सीधे गोरेगांव की फिल्मसिटी में बुलाया। वहाँ जाने पर मैं एक बड़ा सेट देखकर चौंक गया, जहाँ हजारों लोग थे। फिर मिस्टर हीरानी ने बताया कि वे पंजाब के एक जाने-माने थियेटर आर्टिस्ट के साथ एक दृश्य की शूटिंग करने वाले थे, लेकिन किसी कारण से वह अपना किरदार निभाने नहीं आ पाया। वह फिल्म की शूटिंग का पहला दिन था और मिस्टर हीरानी प्रोडक्शन को रोकना नहीं चाहते थे। चूंकि वह फिल्म का पहला दिन था और राजकुमार हीरानी जी कोई बाधा नहीं चाहते थे, इसलिये उन्हें तुरंत मेरा खयाल आया, क्योंकि हम पहले भी साथ में काम कर चुके थे। फिर राजू सर ने मुझे अपनी फिल्म 'डंकी' में लालटू का रोल दिया, जोकि एक नकली पंजाबी वीजा एजेंट है। मैंने खुशी से वह भूमिका स्वीकार कर ली। उन्होंने मुझे किरदार और सीन के बारे में समझाया, ताकि मैं पंजाबी उच्चारण का अभ्यास

कर सकूं। शूटिंग के बाद राजकुमार जी ने मेरे घर एक बड़ा-सा गुलदस्ता भेजा और अपना आभार जताया। उनका यह तरीका मुझे बेहतरीन लगा।''

राजकुमार हीरानी के साथ अपने ताल-मेल के बारे में उन्होंने बताया, ''मैं उनसे पहली बार 1997 में मिला था, जब डीडी1 पर उनके एक शो का ऑडिशन देने मुंबई आया था। दुर्भाग्य से वह शो कभी पर्दे पर नहीं आ सका। हालांकि राजकुमार ने भविष्य में अपने प्रोजेक्ट्स के लिये मुझे आश्वासन दिया था और 'डंकी' ऐसा ही एक प्रोजेक्ट रहा। मैंने हीरानी जी के साथ उनकी मशहूर एंथोलॉजी सीरीज 'द बेस्टसेलर्स' में काम किया था और उसमें मेरी मुख्य भूमिका थी। तब से हमारा रिश्ता मजबूत है। 'डंकी' के लिये शूटिंग के दिन का अनुभव खुशनुमा था। हीरानी जी ने मेरा परिचय फिल्म के लेखक अभिजात जोशी और अभिनेत्री तापसी पन्नू से करवाया। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, जब तापसी ने 'भाबीजी घर पर हैं' के लिये मुझे पहचाना और बताया कि उन्हें हमारा शो बहुत पसंद है। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे ऐसी बड़ी फिल्म में एक रोल मिलेगा और सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा (हंसते हैं)। मेरे लिये वह सचमुच एक बेहतरीन संयोग और शानदार अनुभव था।''

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

नासिक में 22 को कालाराम मंदिर के दर्शन करेंगे : उद्धव

मुंबई। प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि वह और उनकी पार्टी के नेता 22 जनवरी को नासिक के कालाराम मंदिर के दर्शन करेंगे और गोदावरी नदी के किनारे 'महा आरती' करेंगे। ठाकरे को 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अभी तक कोई निमंत्रण नहीं मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी मां दिवंगत मीना ठाकरे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद यहां पत्रकारों से कहा कि जब भी उनका मन करेगा तो वह अयोध्या जाएंगे। उन्होंने कहा, ''अयोध्या के राम मंदिर का अभिषेक गौरव और आत्म-सम्मान का विषय है। उस दिन (22 जनवरी), हम शाम साढ़े छह बजे कालाराम मंदिर के दर्शन करेंगे जहां डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर और समाज सुधारक साने गुरुजी को विरोध प्रदर्शन करना पड़ा था। शाम साढ़े सात बजे हम गोदावरी नदी के किनारे पर महा आरती करेंगे।'' नासिक के पंचवटी इलाके में स्थित कालाराम मंदिर भगवानराम को समर्पित है।

कांग्रेस के लिए सीएम का मतलब करप्ट मंत्री : भाजपा

नई दिल्ली। महादेव बेटिंग एप मामले में ईडी के चार्जशीट में और आरोपी द्वारा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम लिए जाने पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जहां भी कांग्रेस की सरकार है, पार्टी उन जगहों को लूटती रहती है। शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस पार्टी उन सभी जगहों को लूटती है, जहां उनकी सरकार है। कांग्रेस के लिए सीएम का मतलब केवल मुख्यमंत्री नहीं है। उनके लिए इसका मतलब करप्ट मंत्री (भ्रष्ट मंत्री) होता है। अब सवाल यह है कि भूपेश बघेल ने ये पैसा आगे किसे दिए? एक तरफ पीएम मोदी देश के लोगों को रुपे कार्ड दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी और राहुल गांधी भूपे कार्ड देते हैं। इस कार्ड का मतलब है कि 508 करोड़ रुपये ट्रांसफर करें और भ्रष्टाचार एवं लूट में शामिल हो जाए। भाजपा नेता ने कहा, जब हम दुनिया के तानाशाहों के बारे में बात करते हैं तो हमें युगांडा के ईदी अमीन का ख्याल आता है।

राशन घोटाले में फंसे टीएमसी नेता शंकर आद्या गिरफ्तार

कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल में कथित राशन घोटाले के सिलसिले में बनगांव नगर निकाय के पूर्व अध्यक्ष शंकर आद्या को शनिवार तड़के गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक, उत्तर 24 परगना जिले के तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता शंकर को एजेंसी ने उनके और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़ी संपत्तियों पर छापेमारी के बाद बनगांव के सिमुलटोला में उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि छापेमारी शुक्रवार को कम से कम 17 घंटे तक चली। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के बाद अधिकारी जब शंकर को ले जाने लगे तो शंकर के समर्थकों ने उनका रास्ता रोकने की कथित तौर पर कोशिश की और अधिकारियों के वाहनों पर पथराव भी किया। अधिकारियों ने बताया कि ईडी टीम के साथ मौजूद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों को हालात पर काबू पाने के लिए भीड़ पर लाठीचार्ज करना पड़ा।

राजनीति की पिच पर दो हफ्ते भी नहीं टिके अंबाती रायुडू

नई दिल्ली। भारत के पूर्व बल्लेबाज अंबाती रायुडू को राजनीति रास नहीं आई। वह दो हफ्ते तक भी इस पिच पर नहीं टिक पाए। 28 दिसंबर को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले अंबाती रायुडू ने छह जनवरी को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने शनिवार को पार्टी छोड़ने और थोड़े समय के लिए राजनीति से दूर रहने की घोषणा की। अपने अचानक लिए गए फैसले के पीछे का कारण बताए बिना रायुडू ने कहा कि वह उचित समय पर अपने अगले कदम के बारे में बताएंगे। अंबाती रायुडू ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, मैं सभी को सूचित करना चाहता हूं कि मैंने वाईएसआरसीपी पार्टी छोड़ने और कुछ समय के लिए राजनीति से बाहर रहने का फैसला किया है। आगे के फैसलों के बारे में उचित समय पर अवगत कराया जाएगा। मई 2023 में अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग्स की जीत के बाद आईपीएल से संन्यास लेने वाले रायुडू पिछले हफ्ते आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी में शामिल हुए थे।

आंध्रप्रदेश में टीडीपी से गठबंधन को लेकर असमंजस में भाजपा

हैदराबाद। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इस बात को लेकर असमंजस में है कि तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) से हाथ मिलाया जाए या नहीं, जिसने आगामी चुनाव के लिए प्रसिद्ध अभिनेता पवन कल्याण की जन सेना पार्टी के साथ गठबंधन किया है। राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। गुरुवार को विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सचिव (संगठन) शिव प्रकाश की अध्यक्षता में भाजपा की केंद्रीय कोर समिति की राज्य भाजपा नेताओं के साथ बुलाई गई बैठक में चुनाव में पार्टी की रणनीति पर मिली-जुली राय थी-कि क्या अकेले जाना चाहिए या टीडीपी-जनसेना गठबंधन में शामिल होना चाहिए। भाजपा पहले से ही जन सेना पार्टी के साथ गठबंधन में है जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का हिस्सा है। लेकिन वह टीडीपी के साथ गठबंधन बहाल करने की इच्छुक नहीं है, जो मार्च 2018 में ही भगवा पार्टी से अलग हो गई थी और नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान एपी के साथ हुए अन्याय के बहाने एनडीए से बाहर आ गई थी।

विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे की चुनौती, टीएमसी बोली-

बात नहीं बनी तो अकेले चुनाव लड़ने को तैयार

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के लिए उसका ''दिल खुला'' है लेकिन अगर बातचीत विफल रहती है तो वह अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि सीट बंटवारे के बारे में कांग्रेस के स्थानीय नेता क्या सोच रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अंतिम निर्णय दोनों दलों के शीर्ष नेताओं द्वारा लिया जाएगा। उन्होंने कहा, ''हमारी नेता ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि कांग्रेस के लिए हमारा दिल खुला है। अब, वे क्या करेंगे यह उन पर निर्भर है। पश्चिम बंगाल में गठबंधन होगा या नहीं, इसका फैसला सोनिया गांधी और ममता बनर्जी करेंगी। स्थानीय कांग्रेस नेता क्या सोचते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।''

तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की यह टिप्पणी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के उस बयान के दो दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी से सीट की भीख नहीं मांगेगी। तृणमूल कांग्रेस के एक अन्य वरिष्ठ नेता ने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा कि पार्टी पश्चिम बंगाल में गठबंधन के लिए तैयार है लेकिन जरूरत पड़ने पर वह अकेले भी चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है। पार्टी के कई नेताओं ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस राज्य की 42 लोकसभा सीट में से चार सीट कांग्रेस के लिए छोड़ने पर विचार कर रही है। साल 2019 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 22 सीट, कांग्रेस ने दो सीट और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राज्य में 18 सीट हासिल की थी। लोकसभा में कांग्रेस के नेता चौधरी ने मुर्शिदाबाद जिले की बहरामपुर सीट से जीत दर्ज की थी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अबू हासिम खान चौधरी ने पड़ोसी मालदा जिले की मालदा दक्षिण सीट से लगातार तीसरी जीत हासिल की थी।

तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष बनर्जी ने इससे पहले पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस और वाम दलों के बीच गठबंधन का भरोसा जताया था। इस 'प्रस्ताव' को उनकी धुर विरोधी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने तत्काल खारिज कर दिया था और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इसकी आलोचना की थी। कुछ दिन बाद, उन्होंने दोनों दलों पर भाजपा के साथ हाथ मिलाने का आरोप लगाते हुए

कहा कि यह तृणमूल कांग्रेस ही है जो पश्चिम बंगाल में भगवा खेमे का मुकाबला करेगी। तृणमूल कांग्रेस ने इससे पहले 2001 के विधानसभा चुनाव, 2009 के लोकसभा चुनाव और 2011 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था।

महागठबंधन में सहज नहीं महसूस कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश

बिहार की राजनीति के जानकारों का कहना है कि विपक्ष के इंडी गठबंधन में दाग लग चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ बहुत सहज नहीं महसूस कर रहे हैं क्योंकि राजद अब भी नहीं बदली है। इसलिए देखना होगा कि वह 14- 15 जनवरी को 'चूड़ा दही' के बाद क्या करेंगे? उल्लेखनीय है कि मकर संक्रांति के मौके पर बिहार में सियासी दलों और नेताओं में 'चूड़ा दही' पार्टी देने की परंपरा रही है। 14 जनवरी को किस नेता की पार्टी में कौन शामिल हुआ है, उससे कई बार भविष्य की राजनीति की तस्वीर भी दिखती है। ऐसे में बिहार में महागठबंधन में दरार की खबरों के बीच राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है, इस लिहाज से भी इस साल मकर संक्रांति की पार्टी खास हो सकती है। बता दें कि बिहार में सरकार का नेतृत्व कर रही जदयू में बड़ा बदलाव हो गया है। पार्टी की कमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथों में ले ली है। लोकसभा चुनावों के पहले के इस बदलाव को नीतीश का बड़ा कदम माना जा रहा है। दावा किया गया कि ललन सिंह को उनके पद से हटाने की वजह उनकी राजद प्रमुख लालू यादव के साथ बढ़ती निकटता है।

अपने ओल्ड गार्ड को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में कांग्रेस

नईदिल्ली। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही लोकसभा चुनाव के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहती हैं। भगवा पार्टी इस महीने के अंत तक बड़े चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर सकती है और कई राज्यसभा सांसदों को 2024 का प्रमुख चुनाव लड़ाने की योजना बना रही है। कांग्रेस की भी ऐसी ही योजना है। हालाँकि, दोनों पार्टियों की सोच में बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। चूंकि कांग्रेस में राज्यों के लिए नए नामों और प्रभारियों की घोषणा की गई थी, इसलिए योजना यह सुनिश्चित करने की थी कि वे पार्टी में जान फूंक सकें, जो खासकर राज्य चुनाव के खराब नतीजों से टूटती नजर आ रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि बड़े पैमाने पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा से इसमें मदद मिलेगी, राहुल गांधी उन क्षेत्रों में यात्रा करेंगे जहां सबसे पुरानी पार्टी कमजोर है और कार्यकर्ता निराश हैं। इसके अलावा एक और योजना है कि कई वरिष्ठ लोगों को, जिनका जनाधार अच्छा हो और हाई प्रोफाइल हो, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कहा जा सकता है। युवाओं में से कई लोगों को भी ऐसा करने के लिए कहा जा सकता है। हालाँकि, अड़चन यह है कि बहुत से नेता उत्सुक नहीं हैं। सूत्रों का कहना है कि भूपेश बघेल, टीएस सिंह देव और अशोक गहलोत जैसे पूर्व मुख्यमंत्री इस पद के लिए इच्छुक नहीं हैं। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों में समस्या उम्मीदवारों को ढूंढने की है। यूपी की तरह, जबकि कांग्रेस ने सीट-बंटवारे की बातचीत के दौरान कम से कम 10 सीटों पर दावा किया है, उसे प्रयागराज, अमेठी और रायबरेली के अलावा कोई और सीट मिलना मुश्किल हो सकता है। कांग्रेस ने भी कहा है कि कम से कम 290 सीटों पर उसकी सीधी लड़ाई बीजेपी से है और उसे अकेले लड़ने का मौका दिया जाना चाहिए। हालाँकि, यह कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। उदाहरण के लिए, ओडिशा में, जहां संगठन खस्ताहाल है, उसे ऐसे उम्मीदवार भी नहीं मिलेंगे जो सोचते हों कि वे जीत सकते हैं। यह सबसे पुरानी पार्टी के लिए एक शर्मनाक स्थिति है और दुर्भाग्य से, यह युद्ध के लिए तैयार नहीं दिखती है।

न्याय का हक मिलने तक यात्रा जारी रहेगी: राहुल

खड़गे ने जारी किया भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो

नईदिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होने वाली है, देश के बुनियादी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित होगी। पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को ये बाते कही। खड़गे ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो और टैगलाइन न्याय का हक मिलने तक भी लॉन्च किया। इस दौरान खरगे ने कहा कि भारत जोड़ों न्याय यात्रा, देशवासियों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की ओर हमारा एक मजबूत कदम है। खरगे ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा जब हमने संसद में देश से जुड़े मुद्दे उठाने की कोशिश की तो सरकार ने हमें बोलने नहीं दिया। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। यही वजह है कि हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए लोगों के बीच जा रहे हैं ताकि हम उनकी बात सुन सकें और हमारी बात कह सकें।

उन्होंने कहा कि हम 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में यह यात्रा मणिपुर के इंफाल से शुरू होगी और देश के 15 राज्यों से होकर गुजरेगी और मुंबई में खत्म होगी। यह यात्रा 110 जिलों, 100 लोकसभा सीटों और 337 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा, हम अन्याय और अहंकार के खिलाफ, न्याय का नारा बुलंद करके, अपने ही लोगों के बीच वापस आ रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा का एक वीडियो साझा करते हुए कहा, मैं सच्चाई के इस रास्ते पर चलने की कसम खाता हूं, जब तक मुझे न्याय का अधिकार नहीं मिल जाता, यात्रा जारी रहेगी। राज्य कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने पहले कहा था कि यात्रा 67 दिनों में 6,700 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी। ठाकुर ने कहा कि यात्रा

के 16-17 फरवरी के बाद छत्तीसगढ़ पहुंचने की उम्मीद है और यह पांच दिनों में राज्य के सात जिलों को कवर करेगी, जहां आदिवासियों की आबादी लगभग 32 प्रतिशत है।

उन्होंने कहा, कांग्रेस सत्याग्रह को जनता के अधिकारों की लड़ाई के लिए एक मजबूत हथियार मानती है और भारत जोड़ो न्याय पदयात्रा आजादी के बाद देश का सबसे बड़ा और परिवर्तनकारी सत्याग्रह साबित होगी। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले यात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ में पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना चाहती है क्योंकि पार्टी को राज्य में हाल के विधानसभा चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मणिपुर में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, लेकिन पीएम मोदी वहां जाने के बजाय बीच पर चले गए। स्वीमिंग करते हुए फोटो सेशन कराया। निर्माणाधीन राम मंदिर पर फोटो खिंचाने चले गए या केरल और मुंबई चले गए। वह सभी जगह जा रहे हैं, आप भगवान के दर्शन की तरह सभी जगह उनकी तस्वीरें देख सकते हैं, लेकिन वह मणिपुर क्यों नहीं गए? दरअसल भारत का उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर बीते कई महीनों से जातीय हिंसा से जूझ रहा है। मणिपुर के बहुसंख्यक मैतई समुदाय को जनजातीय आरक्षण का लाभ देने के फैसले के खिलाफ राज्य में हिंसा शुरू हुई थी, जिसमें अभी तक 200 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

वॉर्नर ने पाक पर जीत के साथ टेस्ट क्रिकेट को कहा अलविदा

सिडनी। डेविड वार्नर ने अपने घरेलू मैदान पर 57 रन बनाकर 112 टेस्ट मैच के अपने करियर का अंत किया, जबकि आस्ट्रेलिया ने शनिवार को यहां तीसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को आठ विकेट से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला में क्लीन स्वीप करके इस दिग्गज सलामी बल्लेबाज को शानदार विदाई दी। ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से पाकिस्तान को हराकर सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर लिया। वॉर्नर मैदान पर आए। चेहरे पर एक खिलखिलाती मुस्कान है! अपने साथियों से गले मिले। अंतिम पारी में वार्नर ने 57 रन की पारी खेली और 75 गेंद का सामना किया और 7 चौके लगाए।

उन्होंने तेजतर्रार बल्लेबाजी की और पार्क के चारों ओर शॉट खेले। शानदार अर्धशतक बनाया और अपने घरेलू दर्शकों को यादगार पारी खेलने का मौका दिया! उन्होंने पाकिस्तान को 3-0 से क्लीन स्वीप किया! डेविड वार्नर को अपने अंतिम टेस्ट में मैच जिताऊ रन बनाने का मौका नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने 57 रनों का योगदान दिया।

ऑस्ट्रेलिया ने 130 रनों के अपने विजय लक्ष्य को हासिल कर शनिवार को पाकिस्तान को आठ विकेट से हरा दिया और सीरीज 3-0 से जीत ली। 1995 के बाद से ऑस्ट्रेलिया में लगातार 16 हार के क्रम को समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन हार मिली। अंतिम तीन विकेटों ने 47 रन जोड़े और 115 रन पर आउट हो गए।

प्रारूप से संन्यास लेने से पहले अपना 112वां मैच खेल रहे वार्नर ने बाउंड्री रोप पर सलामी जोड़ीदार और बचपन के दोस्त उस्मान ख्वाजा को गले लगाया और क्रीज पर आते ही पर्यटकों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। ख्वाजा शुरुआती ओवर में शून्य पर पगबाधा आउट हो गए। उन्होंने स्क्वायर लेग पर एक रन लेकर अपना 37वां टेस्ट अर्धशतक पूरा किया।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सरकार अधिक उत्पादों को अनिवार्य गुणवत्ता मानकों के तहत लाएगी : पीयूष गोयल

नईदिल्ली। उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के क्रम में सरकार अन्य उत्पादों को भी अनिवार्य गुणवत्ता मानकों के दायरे में लेकर आएगी। गोयल ने भारतीय मानक ब्यूरो के 77वें स्थापना दिवस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करते हुए कहा कि उत्पादों और सेवाओं में उच्च गुणवत्ता मानकों का अनुपालन करने से भारत को ऊंचा लक्ष्य पाने और एक विकसित राष्ट्र बनने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, इस दिशा में बीआईएस को गुणवत्ता मानकों का दूत बनना चाहिए। इसे केवल मानकों को अपनाने वाला नहीं बनना चाहिए, बल्कि मानकों का अगुवा भी बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी तक 672 उत्पादों को दायरे में लाने वाले 156 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किए जा चुके हैं।

5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारी को एक मार्च से हो सकती है दिक्कत

नईदिल्ली। पांच करोड़ रुपये से अधिक कारोबार वाले व्यवसाय एक मार्च से सभी कारोबारी लेनदेन के लिए ई-चालान दिए बगैर ई-वे बिल जारी नहीं कर पाएंगे। जीएसटी प्रणाली के तहत 50,000 रुपये से अधिक कीमत के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने के लिए ई-वे बिल रखना जरूरी होता है। राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र ने विश्लेषण के आधार पर पाया है कि ई-चालान के लिए कुछ पात्र करदाता बी2बी (फर्म से फर्म को) और बी2ई (कंपनियों से निर्यातकों को) के लेनदेन के लिए ई-वे बिल ई-चालान से जोड़े बगैर ही बना दे रहे हैं। इनमें से कुछ मामलों में, ई-वे बिल और ई-चालान के तहत अलग-अलग दर्ज चालान विवरण कुछ मापदंडों में मेल नहीं खा रहे हैं। इससे ई-वे बिल और ई-चालान विवरण के बीच मिलान नहीं हो रहा है।

सेवा क्षेत्र की गतिविधियां तीन माह के उच्चतम स्तर पर

नई दिल्ली। सेवा क्षेत्र की गतिविधियां बेहतर आर्थिक परिस्थितियों और सकारात्मक मांग के दम पर दिसंबर में तीन महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। मौसमी रूप से समायोजित एचएसबीसी इंडिया भारत सेवा पीएमआई कारोबारी गतिविधि सूचकांक दिसंबर में 59 पर पहुंच गया। यह नवंबर में 56.9 पर था। खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) का 50 से ऊपर रहने का मतलब गतिविधियों में तेजी बनी हुई है। 50 से कम अंक का आशय कमजोरी से होता है। यह सर्वेक्षण सेवा क्षेत्र की 400 कंपनियों के साथ सवाल-जवाब पर आधारित है। मांग में उछाल से बिक्री में तेजी आई जिससे कारोबारी गतिविधियां भी बढ़ीं। रोजगार निर्माण 19वें महीने बढ़ा। एचएसबीसी इंडिया कंपोजिट पीएमआई आउटपुट इंडेक्स 57.4 से बढ़कर 58.5 हो गया। एचएसबीसी की भारत में मुख्य अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी ने कहा, भारत का सेवा क्षेत्र उच्च स्तर पर रहा है।

सल्फर कोटेड यूरिया की कीमत 266.50 रुपये होगी

नई दिल्ली। सरकार ने सल्फर लेपित यूरिया को यूरिया गोल्ड के नाम से लॉन्च करने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रसायन व उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग ने सभी उर्वरक विनिर्माण कंपनियों के एमडी/सीएमडी को अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है। विभाग ने अधिसूचना में बताया है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 28 जून, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में यूरिया गोल्ड के नाम से सल्फर लेपित यूरिया लॉन्च करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में, सक्षम प्राधिकारी ने 40 किलोग्राम के बैग में सल्फर लेपित यूरिया को नीम लेपित यूरिया के 45 किलोग्राम बैग के समान एमआरपी पर शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इसकी कीमत जीएसटी सहित 266.50 रुपये होगी।

2023 में भारत की आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धि लंबे समय तक याद रखी जाएंगी

(गतांक से आगे...)

प्रह्लाद सबनानी

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए एक अनुपालन प्रतिवेदन में बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की द्वितीय तिमाही, जुलाई-सितंबर 2023, में भारत का चालू खाता घाटा 830 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि से कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का एक प्रतिशत रह गया है। यह वित्तीय वर्ष 2022-23 की द्वितीय तिमाही, जुलाई-सितम्बर 2022, में 3000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का रहते हुए सकल घरेलू उत्पाद का 3.8 प्रतिशत था। भारत के विदेशी व्यापार के मामले में यह एक अतुलनीय सुधार दृष्टिगोचर हुआ है। चालू खाता घाटा किसी भी देश के वस्तुओं और सेवाओं के आयात एवं निर्यात के मूल्य के साथ साथ वित्तीय हस्तांतरण के बीच के अंतर को मापता है। चालू खाता घाटे का कम होना किसी भी देश के लिए अच्छी स्थिति कही जाती है क्योंकि इससे मजबूत हो रहे निर्यात एवं कम हो रहे आयात की स्थिति का पता चलता है।

वर्ष 2023 में भारतीय बैंकों विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के बैंकों में गैर निष्पादनकारी आस्तियों का स्तर लगभग न्यूनतम स्तर पर आ गया है और पूंजी पर्याप्तता अनुपात लगभग उच्चत्तम स्तर पर आ गया है। कई बैंकों में तो यह स्तर अमेरिकी बैंकों के पूंजी पर्याप्तता अनुपात से भी अधिक है। कुछ वर्ष पूर्व तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पूंजी पर्याप्तता अनुपात को अंतरराष्ट्रीय स्तर के मानकों पर बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार को इन बैंकों में पूंजी डालनी होती थी परंतु आज सरकारी क्षेत्र के बैंक केंद्र सरकार को भारी भरकम लाभांश की राशि का भुगतान कर रहे हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में तो जैसे टर्न अराउंड ही दिखाई देता है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक अन्य प्रतिवेदन के अनुसार, भारत के विभिन्न राज्यों की बजटीय स्थिति एवं इनके राजकोषीय स्वास्थ्य में लगातार मजबूती दिखाई दे रही है। विभिन्न राज्यों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में किए गए सुधारों को जारी रखा है, जिसके चलते राज्यों का संयुक्त राजकोषीय घाटा नियंत्रण में रहते हुए कम हुआ है। केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्यों के राजकोषीय घाटे पर, कोविड महामारी के बाद अत्यधिक दबाव पैदा हो गया था परंतु इसके बाद से लगातार स्थिति में सुधार हुआ है। मुख्य रूप से कर संग्रहण के अनुपालन में सुधार करते हुए कर संग्रहण में पर्याप्त वृद्धि हुई है एवं कुछ राज्यों द्वारा खर्चों पर नियंत्रण भी किया जा सका है, हालांकि पूंजीगत व्ययों को प्रभावित नहीं होने दिया गया है, जिसके कारण राजकोषीय घाटे की स्थिति में सुधार दिखाई देने लगा है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने उक्त प्रतिवेदन में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विभिन्न राज्यों के बजट, राजकोषीय संकेतक एवं व्यय के पैटर्न का विश्लेषण किया है। मुख्य बिंदु जिन पर सुधार बताया गया है उनमें शामिल हैं, वस्तु एवं सेवा कर के संग्रहण में लगातार हो रहा सुधार, राजस्व घाटे में आ रही कमी, पूंजीगत व्यय में लगातार हो रही वृद्धि और बकाया ऋण स्तर में कमी होना, बताया गया है। राज्य स्तर पर आगे आने वाले समय में मजबूत आर्थिक विकास और राजकोषीय सुधारों द्वारा राज्यों की समग्र बजटीय स्थिति सकारात्मक होने का अनुमान इस प्रतिवेदन में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाया गया है। इस स्थिति को भारत के लिए राहत देने वाली माना जा सकता है। राज्यों का राजस्व घाटा कम होने के कारण राज्यों का संयुक्त राजकोषीय घाटा लगातार दूसरे वर्ष लक्ष्य के मुकाबले सकल घरेलू उत्पाद का 2.8 प्रतिशत पर सीमित रहा है। पूंजी निवेश समर्थन के लिए केंद्रीय योजना के नेतृत्व में वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में पूंजीगत व्यय में 52.6 प्रतिशत की आकर्षक वृद्धि दर्ज हुई है। राजस्व व्यय वृद्धि में कमी आई है और व्यय की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में बकाया देनदारियां वित्तीय वर्ष 2011 में 31 प्रतिशत से घटकर वित्तीय वर्ष 2024 में 27.6 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है।

कही-सुनी

रवि भोई

अफसरों की पोस्टिंग से भाजपा में खलबली

कहते हैं आईएएस और राज्य सेवा अफसरों की पोस्टिंग से भाजपा में खलबली मच गई है। विष्णुदेव साय सरकार में अफसरों की पोस्टिंग में किसकी चली, इसको लेकर कयासों का बाजार गर्म है। चर्चा है कि आईएएस अफसरों की पोस्टिंग में साय सरकार के एक मंत्री और मुख्यमंत्री सचिवालय के एक अफसर की खूब चली। कहा जा रहा है कि दोनों ने न भाजपा नेताओं की सिफारिश सुनी और न ही संघ की पसंद और नापसंद का ध्यान रखा। मंत्रियों से भी राय-मशविरा नहीं की। पोस्टिंग लिस्ट बनाने वाले ने अपने गृह राज्य और स्वजातीय लोगों का खास ख्याल रखा है। इलाके और संवर्ग का फायदा भी अफसरों को मिला है। साय सरकार में 88 आईएएस अफसरों की पहली पोस्टिंग में कइयों को झटका लगा है, तो कइयों के पंख भी लगे हैं। कुछ का भला भी हुआ है। अफसरों की पहली पोस्टिंग में विषमता और असंतुलन भाजपा नेताओं को चुभ रहा है। पहली पोस्टिंग में भाजपा के टारगेट में कुछ अफसरों को लूप लाइन में पटका जरूर है, लेकिन कई अफसरों को मलाईदार पद भी मिल गया है। चुनाव आयोग के निशाने पर आए तारण सिन्हा को नए आर्डर में लूप लाइन में भेज दिया गया है, जबकि संजीव कुमार झा को समग्र शिक्षा का संचालक बना दिया गया है। खबर है कि समग्र शिक्षा के लिए भारत सरकार से खूब फंड मिलता है। भाजपा नेता महेश गागड़ा के निशाने पर रहे आईएएस राजेंद्र कुमार कटारा को बीजापुर के कलेक्टर पद से हटा तो दिया गया, लेकिन एस सी ई आर टी का प्रमुख बना दिया गया, उन्हें रायपुर कलेक्टर रहे भूरे सर्वेश्वर नरेंद्र और दुर्ग कलेक्टर रहे पुष्पेंद्र कुमार मीणा की तरह दरकिनार नहीं किया गया। नारायणपुर कलेक्टर रहते भाजपा के जिला अध्यक्ष के प्रति बेरहमी दिखाने वाले अजीत वसंत का कद बढ़ना भी भाजपा के कुछ नेताओं को साल रहा है। नए आर्डर में अजीत वसंत को कोरबा का कलेक्टर बनाया गया है। महतारी वंदन योजना का फार्म बंटवाने पर भाजपा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने और एक भाजपा कार्यकर्ता को दफा 151 के तहत गिरफ्तार करवाने वाले बलौदाबाजार-भाटापारा कलेक्टर चंदन कुमार का बालबांका न होने पर भाजपा नेताओं ने सिर पकड़ लिया है।

जांजगीर-चांपा जिले की तीनों विधानसभा सीट में कांग्रेस की जीत के बाद भी वहां कलेक्टर रही ऋचा प्रकाश चौधरी को दुर्ग की कलेक्टर बनाए जाने पर भाजपा नेताओं ने दांतों तले अंगुली दबा लिया है। सक्ती जिले की तीनों सीटों में भाजपा की हार के बाद भी वहां की कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना के प्रति मेहरबानी भाजपा नेताओं को समझ नहीं आ रहा है। शम्मी आबिदी को महिला एवं बाल विकास विभाग का सचिव बनाए जाने पर भी भाजपा के नेताओं को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आईएएस मोहम्मद कैसर अब्दुल हक़ और डॉ तम्बोली अय्याज फकीर भाई की नई पोस्टिंग भी भाजपा नेताओं को रास नहीं आ रहा है। साय सरकार ने धार्मिक धर्मस्व विभाग को काफी महत्व दिया है। इस विभाग में अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू की पोस्टिंग के साथ पी अंबलगन को सचिव बनाए रखा है।गृह विभाग में अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ के बाद लाइन खाली हो गया है, जबकि गृह महत्वपूर्ण विभाग है। शहला निगार को कृषि उत्पादन आयुक्त बनाए जाने को कृषि मंत्री रामविचार नेताम पर नकेल कसने के रूप में देखा जा रहा है।कृषि संचालक भी महिला आईएएस चंदन त्रिपाठी हैं। टीएस सिंहदेव की करीबी रहीं, फिर भूपेश बघेल की सरकार में उपेक्षित निहारिका बारीक सिंह को साय सरकार में इनाम मिल गया, उन्हें बड़ा और महत्वपूर्ण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सौंपा गया है। पिछली सरकार में दरकिनार आर. शंगीता को आबकारी के साथ आवास और पर्यावरण विभाग के साथ पर्यावरण मंडल की अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी मिल गई है, पर सरकार ने अभी तक किसी को आबकारी आयुक्त नियुक्त नहीं किया है, जबकि आबकारी विभाग में आयुक्त का रोल ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्रतिनियुक्ति से वापसी के बाद लंबे समय तक प्रमुख सचिव के मातहत अफसर बने रहे बसवराजू एस के भी बल्ले-बल्ले हो गए। खाद्य और नगरीय प्रशासन जैसा महत्वपूर्ण विभाग देकर उनका अच्छा पुनर्वास कर दिया गया है। आर्डर में कई विभागाध्यक्ष अछूते रह गए तो हेरफेर में कई पद खाली रह गए हैं। पद भरने और नए विभागाध्यक्ष का इंतजार है।

मंत्री जी की मैराथन बैठक से अफसर परेशान

चर्चा है कि पिछले दिनों राज्य के एक मंत्री जी ने मंत्रालय के एक कांफ्रेंस हाल में अपने विभाग के अफसरों की मैराथन बैठक ली। मंत्री

जी मलमास के चलते मंत्रालय के अपने कक्ष में अब तक प्रवेश नहीं किया है। कहते हैं मंत्री जी को किसी ज्योतिष ने कह दिया है कि मलमास में कक्ष में प्रवेश करना शुभ नहीं होगा। मंत्री जी के पास बड़े -छोटे कई विभाग हैं। समीक्षा बैठक करते -करते सुबह के पांच -साढ़े पांच बज गए। बताते हैं मंत्री जी ने बैठक के लिए विभाग के अफसरों को दोपहर से ही बुला लिया था। मंत्री जी को रत जगा की आदत है, पर रात भर चली बैठक से अफसर परेशान हो गए। कहा जा रहा है कि अफसर रात-रात भर चलने वाली बैठक से निजात पाना चाहते हैं। इसके लिए वे मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहते हैं। कुछ अफसर मंत्री जी के विभाग से अपने ट्रांसफर की जुगाड़ में लग गए हैं।

पूरे घर के बल्ब बदल गए

असरानी के घर का एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो वे बल्ब खरीदने निकल पड़ते हैं। दुकानदार उनको बल्ब-ट्यूब बनाने वाली पॉपुलर ब्रांड और कंपनी के बल्बों के टिकाऊपन के बारे में बताता है, तो जोश में आकर वह बोल उठते हैं 'पूरे घर के बदल डालूंगा!' असरानी के विज्ञापन पूरे घर का बदल डालूंगा की तर्ज पर राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग के अफसर बदल दिए गए। प्रमुख सचिव रहे आलोक शुक्ला पहले ही इस्तीफा देकर चले गए थे। तीन जनवरी को जारी आईएएस अफसरों के तबादला आदेश में सचिव, संचालक और प्रबंध संचालक सभी बदल दिए गए। पिछली सरकार में स्कूल शिक्षा विभाग काफी चर्चित रहा। शिक्षकों की भर्ती और पोस्टिंग को लेकर बड़ा बवाल मचा था। पूरे घर के बदलने के बाद नई सरकार में विभाग कितना पाक -साफ़ हो सकता है, इसका सबको इंतजार है।

फिर लार टपकने लगा

2003 से 2018 तक आबकारी विभाग का माई -बाप बने एक संविदा अफसर का राज्य में भाजपा की सरकार सत्ता में आते ही लार टपकने लगा है। कांग्रेस राज में धक्के खाने और जांच में उलझे संविदा अफसर पुनर्नियुक्ति के लिए कुशाभाऊ ठाकरे परिसर ,जागृति मंडल, राममंदिर,पहुना, मौलश्री विहार से दिल्ली दरबार तक जुगाड़ फिट करने में जुट गए हैं। पिछली सरकार में संविदा अफसर की तूती बोलती थी। कांग्रेस राज में संविदा अफसर की जगह त्रिपाठी महाशय ने ले ली थी, जो जेल की सलाखों के पीछे हैं। संविदा अफसर भी काफी दागदार हो चुके हैं। अब देखने वाली बात है कि भाजपा सरकार कोयले को छूकर हाथ गंदा करना चाहती है या पाक-साफ रहना चाहती है।

विधायक जी की बकरा पार्टी

कहते हैं दुर्ग जिले के एक नए-नवेले विधायक जी ने अपनी जीत की खुशी में पिछले दिनों एक फार्म हाउस में बकरा पार्टी आयोजित की। इस पार्टी में अपने खास समर्थकों के साथ अपने इलाके के पीडब्ल्यूडी के अफसरों को भी न्योता था। पार्टी के बाद विधायक जी ने पीडब्ल्यूडी के अफसरों से अपने महीने की चर्चा छेड़ी और भारी-भरकम मांग रख दी। चर्चा है कि विधायक जी की मांग सुनकर पीडब्ल्यूडी के अफसरों के पैर के नीचे की जमीन ही खिसक गई। कुछ तो उलटे पांव भागे, कुछ विधायक जी को समझाने में लगे।

रंग बदलने वाले कारोबारी

कहते हैं राजधानी के एक कारोबारी गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। 2018 के पहले तक भाजपा और कई खेल संघों से जुड़े कारोबारी कांग्रेस की सरकार आते ही पाला बदल लिया था। अब भाजपा की सरकार आई तो फिर मुख्यमंत्री,मंत्री और विधायकों के पास गुलदस्ता लेकर पहुंच गए। कोरोना काल में खूब चांदी काटने वाले कारोबारी पिछली सरकार में ताकतवर एक व्यक्ति की पूंछ पकड़ ली थी। कारोबारी के करतूत से जनता सड़क पर उतर आई थी ,जिसके बाद पिछली सरकार को कारोबारी से दूरी बनानी पड़ी थी। अब भाजपा सरकार में ठौर की तलाश में हैं।

मनहूस बंगला

राजधानी के सिविल लाइन में एक बंगला है, जिसे इस बार कोई भी मंत्री लेना नहीं चाहता था। बंगला बड़ा और प्राइम लोकेशन में है, लेकिन इसके साथ हार का किस्सा जुड़ गया है। इस बंगले में जो भी मंत्री अब तक रहा है, वह जीतकर दोबारा नहीं आया है या फिर मंत्री नहीं बन पाया है। इस कारण साय सरकार का कोई भी मंत्री उस बंगले में नहीं जाना चाहते थे। बंगला बड़ा और अच्छा होने के कारण किसी न किसी मंत्री को तो देना ही था। यह बंगला अब पहली बार विधायक और मंत्री बने नेता के हिस्से में आया है। अब अगली बार नेता जी का भविष्य पता चलेगा।

मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने स्वास्थ्य मंत्री से सौजन्य भेंट की

जायसवाल ने मेकाहारा के उन्नयन का दिलाया भरोसा

रायपुर। चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के कार्यकारिणी सदस्यों ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से उनके निवास पर सौजन्य भेंट की। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पुष्पगुच्छ प्रदान कर उनका स्वास्थ्य मंत्री बनने पर अभिनंदन किया और सक्रिय, विकासशील और उद्देश्यपूर्ण कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं व्यक्त की। इस

अवसर पर मंत्री ने उम्मीद जाहिर की, कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं जिला अस्पतालों का इस तरह उन्नयन किया जायेगा कि आने वाले समय में मंत्री, विधायक, शासकीय अधिकारी एवं सुरक्षा से जुड़े हुए जवान अपना इलाज इन्हीं अस्पतालों में करायें। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले कुछ दिनों में वे चिकित्सा शिक्षकों के साथ विशेष बैठक पर उनकी और चिकित्सा महाविद्यालयों की समस्याओं से अवगत होना चाहेंगे ताकि तदानुसार निराकरण किया जा सके। चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. अरविन्द नेरल ने मानव संसाधनों की कमी, चिकित्सा उपकरण एवं रिएजेन्टस- केमिकल्स की समय पर अनउपलब्धता जैसी मूलभूत समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया।

इस अवसर पर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष द्वय डॉ. देवप्रिय लकड़ा, डॉ. निर्मल वर्मा, सचिव डॉ. जया लालवानी, कार्यकारिणी सदस्य डॉ. मंजू सिंह, डॉ. ज्योति जायसवाल, डॉ. प्रतिभा जैन शाह, डॉ. हंसा बंजारा, डॉ. संतोष सोनकर, डॉ. कमलेश जैन, डॉ. उषा जोशी एवं डॉ. स्निग्धा जैन बंसल उपस्थित थे।

प्रदेश में अब तक 82.44 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के तहत एक नवंबर 2023 से धान खरीदी का महाअभियान निरंतर जारी है। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष मोदी की गारंटी के अनुरूप किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा अब तक किसानों से 82.44 लाख मीट्रिक टन धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा चुकी है। धान के एवज में किसानों को 17,773 करोड़ रूपए से अधिक राशि का भुगतान किया गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान विक्रय का लाभ पूर्व में धान बेच चुके किसानों को भी मिलेगा। इसका आशय यह है कि एक नवम्बर से अब तक पूर्व निर्धारित मात्रा के अनुरूप धान बेच चुके किसान, शेष मात्रा का धान, उपार्जन केन्द्र में 31 जनवरी तक बेच सकेंगे। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में राज्य के किसानों से प्रति एकड़ 15 क्विंटल कॉमन धान की 2040 रूपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य की दर से किए जाने के साथ ही उन्हें प्रति एकड़ 9000 रूपए की इनपुट सब्सिडी दी गई, जिसे मिलाकर अधिकतम 39,600 रूपए का भुगतान होता था।

प्रमुख समाचार छत्तीसगढ़/राजधानी

मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को किया जर्जर

रायपुर। विगत दिनों राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी अग्रिम अनुमान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा अपनी नाकामी पर परदेदारी करने के तमाम प्रयासों के बावजूद रिपोर्ट से स्पष्ट है कि देश में कृषि विकास दर विगत वर्ष से 1.6 प्रतिशत कम रही है। कृषि अर्थव्यवस्था देश की रीढ है, लेकीन मोदी सरकार के किसान विरोधी निर्णयों के चलते देश के किसान लगातार बदहाल हो रहे हैं। कृषि उपकरणों पर भारी भरकम जीएसटी, डीजल पर भारी भरकम सेंट्रल एक्साइज, खाद, बीज, दवा सभी महंगी कर दी गई। खाद सब्सिडी विगत बजट के मुकाबले इस बजट में सीधे 35 हजार करोड रुपए कम कर दिया गया। सी 2 फार्मूले पर 50 प्रतिषत लाभ देने के स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू करने का भाजपा का वादा अब तक केवल वायदों में ही है। किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी भी जुमला साबित हो गया। जीडीपी विकास दर भी आम बजट में मोदी सरकार द्वारा लगाए गए अनुमान से लगातार कम हो रहा है, जिसके चलते देश का वित्तिय घाटा 6 प्रतिशत से पार होना संभावित है। मोदी सरकार के गलत आर्थिक नीतियों के चलते देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। देश में महंगाई, वैश्विक महंगाई दर की तुलना में अधिक है।

कोयला घोटालाः फिर कोर्ट में पेश नहीं हुए विधायक देवेन्द्र

रायपुर। विगत कोल लेवी वसूली और मनी लांड्रिंग मामले में ईडी और आरोपियों के आवेदनों पर विशेष न्यायालय में शनिवार को सुनवाई शुरू हुई। हाई प्रोफाइल केस की वजह से जिला कोर्ट परिसर में हलचल देखी जा रही है। जानकारी के अनुसार, ईडी की ओर से जहां मामले के आरोपियों से जेल में पूछताछ की अनुमति के लिए याचिका लगाई गई है. वहीं दूसरी ओर आरोपियों में निलंबित आईएएस रानू साहू और पूर्व सीएम की उप सचिव सौम्या चौरसिया की ओर से स्वास्थ्यगत कारणों से पेश होने से छूट मांगी है। इसके अलावा कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की से दायर अग्रिम जमानत याचिका के साथ कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ ईडी की ओर से गैर जमानती वारंट जारी करने की याचिका पर सुनवाई होगी। बताया जा रहा है कि देवेंद्र यादव के साथ राम गोपाल अग्रवाल दोनों की कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। देवेंद्र यादव के दिल्ली में होने की खबर है, वहीं अग्रवाल के देश से बाहर होने की बात कही जा रही है। रामगोपाल अग्रवाल अब तक ईडी की ओर से जारी चार समन के बाद भी पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं। बीते साल सितंबर और अक्टूबर माह में समन जारी किए गए थे. उन्हें पेश करने के लिए हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी रायपुर पुलिस ने मदद नहीं की थी।

मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति में अधोसंरचना विकास पर विचार-विमर्श

रायपुर। नवा रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में शनिवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और उप मुख्यमंत्री सह विधि एवं विधायी कार्य मंत्री अरूण साव की आधिकारिक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालय के अधोसंरचना विकास तथा कर्मचारियों के विभिन्न पदों के सृजन एवं भर्ती की स्वीकृति से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा अधिकांश प्रस्तावों पर सकारात्मक रूप से विचार करने का आश्वासन दिया गया। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, रजिस्ट्रार जनरल अरविन्द वर्मा, प्रमुख सचिव विधि रजनीश श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, लोक निर्माण विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह, वित्त विभाग के सचिव अंकित आनंद, मुख्य न्यायाधीश के पी.पी.एस. श्री सुब्रमण्यम तथा विधि विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

पांच साल वाले अधिकांश चेहरों का सफाया तय

रायपुर। हार के बाद किन नेताओं की दिल्ली में पूछपरख कम हुई है ये राहुल गांधी का पैमाना नहीं वेणुगोपाल तय कर रहे हैं। दिल्ली में यह स्पष्ट रूप से बात पहुंच चुकी है कि कांग्रेस संगठन के प्रभारी, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री समेत तमाम ओहदेदार नेताओं ने राहुल व प्रियंका को यह बता दिया था कि राजस्थान व एमपी की तो नहीं कहते लेकिन छग में कांग्रेस की सरकार दोबारा बन रही है। फिर भी हार गए। हार के बाद सभी छोटे बड़े नेताओं से वेणुगोपाल ने फीड बैक लिया तो हकीकत सामने आ गई। हालांकि वे इसे सामने नहीं ला रहे हैं इसलिए कि आगे लोकसभा चुनाव है। एक मोहलत के साथ बैज को यथावत रखा गया है जबकि नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा महंत को दिया गया है। गहलोत व भूपेश की जुगलबंदी किसी से छिपी नहीं है,इसलिए सचिन पायलट को आलाकमान द्वारा भेजा जाना छग कांग्रेस में नए समीकरण का संकेत है। जिस प्रकार बस्तर व सरगुजा में सफाया व शहरी इलाकों में भाजपा को मिली बड़ी जीत के मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसे में तो महंत ही बेहतर रहे जो अपने इलाके में लाज बचा ली. एक और बड़ी बात सामने आ रही है कि सिंगल मेन द्वारा प्रत्याशियों की सूची अंतिम समय में तय की गई थी और यही पार्टी से चूक हो गई।

वन विभाग के डिपो में घुसकर बदमाशों ने वनकर्मियों से की मारपीट, दंपत्ति घायल

जशपुर। जिले से बड़ी खबर सामने आई है. आधा दर्जन गुंडे-बदमाशों ने सन्ना के वन परिसर में घुसकर वनकर्मियों के साथ जमकर मारपीट की. इस घटना में घायल वनकर्मी दंपत्ति मुख्यमंत्री के

नजदीकी रिश्तेदार हैं. बताया जा रहा है कि बदमाश लकड़ी चोरी करने गये थे. यह मामला सन्ना थाना क्षेत्र का है. जानकारी के अनुसार, जशपुर जिले के सन्ना वन परिक्षेत्र में स्थित वन विभाग के डिपो में घुसकर कुछ लोग लकड़ी चोरी कर रहे थे. वहां की कमर्चारी चन्दमनी बाई ने मना किया तो उनसे आरोपियों ने पहले मारपीट किया, इसके बाद जब उनके पति वनरक्षक सुधानसाय पैंकरा आये तो सभी बदमाशों ने उनकी भी बेरहमी से पिटाई कर दी. इस हमले से दोनों पति-पत्नी दोनों घायल हो गए हैं. मामले को लेकर वन कर्मचारी संन्ना थाना पहुंच गये हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं. मिली जानकारी अनुसार, शाहनवाज खान,रोहित साहू, रवि भगत, सैफ अंसारी, बबलू ठाकुर,राकेश ताम्रकर वगैरा लोगों ने पूरी घटना को अंजाम दिया है. वहीं मामले में सबसे खास बात ये है कि घटना में पीड़ित कर्मचारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नजदीक के रिश्तेदार हैं.

उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए सबसे ज्यादा पंजीयन

विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों में योजनाओं का लाभ लेने पहुंचे बड़ी संख्या में हितग्राही

रायपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आरंभ की गई जनकल्याणकारी योजनाओं का जनता को लाभ दिलाने आरंभ की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। शिविर के माध्यम से उन लोगों को सीधे योजनाओं का लाभ देने के लिए जोड़ा जा रहा है जो अब तक इनका लाभ नहीं ले पाये हैं। सभी शिविरों में बड़ी संख्या में हितग्राही पहुंच रहे हैं। इन शिविरों की अच्छी बात यह है कि इनमें से सभी शिविरों में मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वाले हितग्राही मेरी कहानी, मेरी जुबानी के माध्यम से बता रहे हैं। लोगों को इनका उचित लाभ मिले, इसके लिए राज्य से मंत्रीगण, विधायकगण और केंद्र के अधिकारीगण भी दौरा कर रहे हैं। शिविरों में सबसे ज्यादा उज्ज्वला योजना और आयुष्मान के बारे में लोग पंजीयन करा रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ लेने भी हितग्राही सामने आ रहे हैं। शिविरों में लोग बता रहे हैं कि पूंजी की सुलभता और

कौशल प्रशिक्षण से उनके लिए उद्यम करना आसान हो गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमें इसके लिए सरकारी कार्यालयों में जाना नहीं पड़ रहा। बीसी सखी से आर्थिक स्थिति मजबूत- कोरिया जिले में बैंकिंग कॉरेस्पांडेंट (बीसी) सखी से जुड़ी श्रीमती कांति प्रजापति का उदाहरण लें। श्रीमती कांति ने बताया कि उन्हें अब 15 से 20 हजार रूपए तक पारिश्रमिक मिलने से घर की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। बता दें बीसी सखी का मुख्य कार्य ग्रामीणों तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाना है, इससे हर तरह के आर्थिक लेनदेन, बैंक खातों में जमा व निकासी, नए खाते खोलने की सुविधा पहुंचाना है। सहायता समूह की महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें बहुत आगे बढ़ने तथा ज्यादा से ज्यादा बचत के महत्व तथा बैंक खोलवाने के बारे जानकारी देने कहा गया। धुआं से छुटकारा और आंखों से आंसू दूर- मेरी कहानी, मेरी जुबानी के तहत जानकारी देते हुए बिलासपुर में श्रीमती रजनी ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत गैस सिलेण्डर मिलने पर उन्हें धुआं से छुटकारा मिलेगी और आंखे सुरक्षित रहेंगी। श्रीमती रजनी ने बताया कि आंखों में इतना धुआँ आता था कि आंखें जलने लगती थीं। कच्चा मकान से मिला छुटकारा, आयुष्मान कार्ड बनी संजीवनी- ग्राम आनी की श्रीमती रमनिया सिंह ने प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) प्राप्त होने पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया, उन्होंने बताया कि कच्चा मकान से छुटकारा मिला अब पक्का मकान मिलने से पानी टपकने की तकलीफ भी दूर हुआ।

माता राजमोहिनी देवी की सेवा भावना सबके लिए प्रेरणा स्त्रोत- श्रीमती राजवाड़े

रायपुर। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने माता राजमोहिनी देवी की पुण्यतिथि पर आज सूरजपुर में पद्मश्री माता राजमोहिनी

देवी स्मृति चौक का लोकार्पण और उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने सूरजपुर जिले के ग्राम जुड़वानी पहुंचकर माता राजममोहनी देवी मंदिर में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पद्मश्री माता राजमोहिनी देवी स्मृति चौक लोकार्पण और प्रतिमा अनावरण समारोह में विशाल जनसमूह को सम्बोधित करते हुए श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि माता राजमोहिनी देवी ने अपना पूरा जीवन समाजसेवा में गुजारा था। उनकी सेवा भावना हम सबके लिए प्रेरणास्त्रोत है। माता राजमोहिनी देवी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन है। इस अवसर पर प्रतापपुर विधायक श्रीमती शकुन्तला सिंह पोर्ते सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिकगण उपस्थित थे।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.